

My Notes.....

राष्ट्रीय

ग्लोबल आईपी इंडेक्स एक पायदान चढ़ा भारत

भारत का प्रदर्शन हालिया अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक (ग्लोबल आईपी इंडेक्स) में बेहतर हुआ है और पिछले साल की तुलना में देश एक पायदान चढ़कर 44वें स्थान पर आ गया है। अमेरिकी उद्योग संगठन यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी सूचकांक के छठवें संस्करण में भारत को 40 में से 12.03 अंक यानी 30 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं।

क्या है

1. पिछले संस्करण में भारत को 35 में से 8.75 अंक यानी 25 प्रतिशत हासिल हुआ था।
2. भारत का प्रदर्शन नये सूचकांकों पर अपेक्षाकृत बेहतर रहा है। इसके साथ ही कंप्यूटर प्रभावी अविष्कारों के पेटेंट तथा पंजीयन प्रक्रिया में सुधार के सकारात्मक प्रयास किये गये हैं।
3. इस सूचकांक में 37.98 अंक के साथ अमेरिका पहले, 37.97 अंक के साथ ब्रिटेन दूसरे और 37.03 अंक के साथ स्वीडन तीसरे स्थान पर रहा है।
4. इस मामले में रपट में भारत की तुलना फिलीपीन और मालदीव जैसे देशों के साथ की गयी है और कहा गया है कि 'इस मामले में ये देश अपने क्षेत्र में बहुत ही खराब हैं'
5. भ्रष्टाचार के मामले में इन देशों के अंक ऊंचे हैं और इनमें प्रेस की आजादी अपेक्षाकृत कम और यहां पत्रकारों की हत्याएं भी ज्यादा हुई हैं।
6. इस सूची में न्यूजीलैंड और डेनमार्क 89 और 88 अंक के साथ सबसे ऊपर हैं। दूसरी तरफ सीरिया, सूडान और सोमालिया क्रमशः 14, 12 और 9 अंक के साथ सबसे नीचे हैं।
7. इस सूची में चीन 77वें और ब्राजील 96वें और रूस 135वें स्थान पर हैं।

इस साल शुरू होगा 'मोदीकेयर'

देश के 10 करोड़ परिवारों यानी करीब 40 फीसदी आबादी को कवर करने वाले सरकार के महत्वाकांक्षी मेगा हेल्थ केयर प्रोग्राम की शुरुआत 2 अक्टूबर से होगी और इसके लिए केंद्र और सभी राज्य मिलकर फंडिंग करेंगे। केंद्र और राज्यों की फंडिंग का अनुपात 60:40 का होगा। प्रति परिवार प्रीमियम पर अनुमानित खर्च 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये होगा। 10 करोड़ परिवार या करीब 50 करोड़ वह आबादी इसके तहत आएगी जिन्हें 2011 के सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना में 'वंचित' की श्रेणी में रखा गया है। यह आधार से लिंकड एक कैशलेस सुविधा होगी और लाभार्थी देश

किन्हें कवर किया जाएगा?

1. 2011 के सोशियो-इकनॉमिक कास्ट सेन्सस में 'वंचित' के तौर पर वर्गीकृत 10 करोड़ परिवार। प्रति परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का कवरेज।
2. एक बार जब योजना लॉन्च हो जाएगी तो ये परिवार खुद-ब-खुद इसके दायरे में आ जाएंगे। परिवार के आकार पर कोई सीमा नहीं है यानी परिवार में चाहे जितने सदस्य हों, सबको कवरेज मिलेगा।
3. स्कीम को लागू करने की टाइमलाइन
4. मार्च तक स्कीम को मंजूरी
5. मार्च तक इससे जुड़े स्टेकहोल्डर्स स्कीम को लेकर मंथन करेंगे।
6. अप्रैल में इससे जुड़े डेटा को तैयार किया जाएगा तो जून तक आईटी सिस्टम की तैयारी हो जाएगी।
7. जून में ही स्कीम को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
8. जुलाई तक इसके लिए राज्य अपनी तैयारियां कर लेंगे और उसी महीने इसके लिए टेंडर निकाला जा सकता है।

में कहीं भी पैनल में शामिल किसी भी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में इलाज करा सकेंगे।

क्या है

1. नीति आयोग ने गणना की है कि हर साल केंद्र पर इस योजना के लिए 10 हजार से 12 हजार करोड़ रुपये का भार आएगा। नीति आयोग को इश्योरेंस कंपनियों की तरफ से बहुत कम प्रीमियम की मदद से इस योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन का भरोसा है।
2. राजस्थान सरकार अभी 500 रुपये प्रति परिवार के प्रीमियम पर सालाना 3.75 लाख रुपये का हेल्थ इश्योरेंस कवर की योजना चला रही है और इसमें क्लेम का रेट करीब 2.5 प्रतिशत है।
3. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में जिस नैशनल हेल्थ प्रॉटेक्शन स्कीम का ऐलान किया था, वह काफी व्यापक है और इसमें इश्योरेंस कंपनियों से मोल-भाव की काफी गुंजाइश है।

राष्ट्रीय कृमि निवारण अभियान

10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस के मौके पर राष्ट्रीय कृमि निवारण अभियान शुरू किया गया। राष्ट्रीय कृमि निवारण अभियान के तहत देश के

32 करोड़ बच्चों को फायदा मिलेगा।

राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में से एक है।

क्या है

1. राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस एक दिन का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता तक पहुँच, पोषण संबंधी स्थिति एवं बच्चों के समग्र स्वास्थ्य में सुधार के लिये बच्चों को परजीवी आंत्र कृमि संक्रमण से मुक्त करने के लिये दवा उपलब्ध कराना है।

पृष्ठभूमि

1. 2015 में राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस की शुरुआत की गई थी, जिसे 11 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिये 1 से लेकर 19 वर्ष की उम्र के बच्चों को ध्यान में रखकर क्रियान्वित किया गया।
2. उसके बाद से पूरे देश में इस कार्यक्रम को लागू किया गया है। पिछले वर्ष फरवरी 2017 के चक्र में 25.6 करोड़ बच्चों और अगस्त 2017 वाले चक्र में 22.8 करोड़ बच्चों तक पहुँचने का सफल प्रयास किया गया और उन्हें राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस पर कृमि निवारण उपचार मुहैया कराया गया।
3. राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस के इस चरण में 32 करोड़ बच्चों तक पहुँचने का लक्ष्य है।
4. जिन राज्यों में STH संक्रमण बीस प्रतिशत से अधिक है वहाँ कृमि मुक्ति के द्विवार्षिक चरण की सिफारिश की जाती है तथा अन्य राज्यों में वार्षिक चरण आयोजित किया जाता है।

2. इस कार्यक्रम में स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के मंच के माध्यम से 1-19 वर्ष की आयु समूह के स्कूल और आंगनवाड़ी से जुड़े सभी बच्चों को शामिल किया जाता है।

3. बच्चों को कृमि मुक्त करने के लिये एलबेंडाजोल नामक टैबलेट दी जाती है।

4. यह कार्यक्रम हर वर्ष 10 फरवरी और 10 अगस्त को आयोजित किया जाता है। अगर कोई भी बच्चा किसी वजह से, खासतौर से गैरहाजिर होने या बीमार होने से राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस में नहीं शामिल हो पाया तो उसे 15 फरवरी को दवा दी जाती है।

5. राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस सभी स्वास्थ्य कर्मियों, राज्य सरकारों और दूसरे हितधारकों को मिट्टी-संचारित कृमि संक्रमण के खतरे के लिये प्रयास करने हेतु प्रेरित करता है।

भारत ने किया एक और स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण

भारत ने सफलतापूर्वक परमाणु सक्षम स्वदेशी अग्नि-I (A) मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण 6 फरवरी 2018 को सुबह 8.30 बजे ओडिशा के बालासोर में अब्दुल कलाम आइलैंड पर किया गया। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इस मिसाइल का परीक्षण भारतीय स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड द्वारा किया गया।

क्या है

1. यह मिसाइल डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है जिसकी मारक क्षमता 700 किमी है। 15 मीटर की ऊंचाई वाली इस मिसाइल में लिक्विड और सॉलिड दोनों तरह के ईंधन का प्रयोग हो सकता है जिसके चलते ही एक सेकंड में 2.5 किमी प्रति घंटे की दूरी तय करती है।
2. हाल में भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। भारत के मिसाइल बेड़े में फिलहाल अग्नि-1, अग्नि-2, अग्नि-3, अग्नि-4 मिसाइलें हैं। जिनकी मारक क्षमता क्रमशः 700 किमी से 3500 किमी की है।

अग्नि-I (A) की खासियत

1. इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है।
2. अग्नि -1 देश की सबसे महत्वाकांक्षी अग्नि श्रृंखला की पहली मिसाइल है जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।
3. भारत ने स्वदेशी अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया
4. इस मिसाइल में लिक्विड और सॉलिड दोनों तरह के ईंधन का प्रयोग हो सकता है।
5. यह एक सेकंड में 2.5 किमी प्रति घंटे की दूरी तय करती है।
6. अग्नि-I की ऊंचाई 15 मीटर है, जिसे दोनों रोड और रेल मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है।
7. मिसाइल का वजन करीब 12 टन है।

फ्लैशपॉइंट

1. अग्नि -I (700 कि.मी. की मारक क्षमता)
2. अग्नि- II (2,000 कि.मी. की मारक क्षमता)
3. अग्नि- III और अग्नि- IV (3,500 किलोमीटर की सीमा से अधिक मारक क्षमता)
4. भारत के पास सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलें भी हैं
5. हाल ही में 26 दिसंबर, 2016 को भारत ने अग्नि- V का सफल परीक्षण किया।

स्टार्ट-अप इंडिया रैंकिंग के लिये फ्रेमवर्क

स्टार्ट-अप की रैंकिंग तय करने के लिये केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा नई दिल्ली में राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के लिये तीन मानक जारी किये गए हैं। ये मानक हैं:- राज्य एवं संघीय क्षेत्र के लिये स्टार्ट-अप रैंकिंग फ्रेमवर्क, भारत में स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिये श्रेष्ठ तरीकों का संग्रह एवं स्टार्ट-अप इंडिया किट।

क्या है

1. भारत में करीब 20,000 स्टार्ट-अप हैं

क्या है स्टार्ट-अप?

1. स्टार्ट-अप एक नई कंपनी होती है, जिसको शुरू करने के बाद उसको विकसित किया जाता है।
2. आमतौर पर स्टार्ट-अप यानी नई कंपनी शुरू करने को कहा जाता है, जिसे कोई व्यक्ति स्वयं या दो तीन लोगों के साथ मिलकर शुरू करता है।
3. आमतौर पर उसको शुरू करने वाला व्यक्ति उसमें पूंजी लगाने के साथ कंपनी का संचालन भी करता है।
4. भारत सरकार, उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "स्टार्ट-अप इंडिया" के नाम से एक योजना की शुरुआत भी कर चुकी है।
5. हाल के कुछ अध्ययनों से यह प्रमाणित हुआ है कि स्टार्ट-अप इंडिया को लेकर लोगों में जागरूकता का अभाव है और इसके लाभार्थियों की संख्या भी बहुत ही कम है।
6. तदोपरान्त, सरकार ने स्टार्ट-अप इंडिया योजना के नियमों में व्यापक परिवर्तन भी किये हैं।

- और करीब 1,400 नए स्टार्ट-अप हर साल शुरू होते हैं। ये न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं, बल्कि प्रत्येक राज्य में तकनीक नवोन्मेष एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देते हैं।
2. उद्यमी प्रतिदिन नए समाधान मुहैया करा रहे हैं या मौजूदा समाधानों में सुधार कर रहे हैं। स्टार्ट-अप की मदद करने एवं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये भारत सरकार ने नीतियाँ बनाने एवं ढाँचा तैयार करने में बढ़त ली है।
 3. 8 राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों ने स्टार्ट-अप और उनके व्यापार करने को अनुकूल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है।
 4. राज्यों एवं संघ क्षेत्रों के लिये स्टार्ट-अप रैंकिंग फ्रेमवर्क तैयार करने का प्रमुख उद्देश्य स्थानीय स्तर पर अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिये राज्यों एवं संघ क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना है।
 5. ये फ्रेमवर्क स्थानीय स्तर पर स्टार्ट-अप के लिये एक प्रभावी वातावरण बनाने के लिये उठाए प्रत्येक कदम के असर को मापेगा। रैंकिंग फ्रेमवर्क श्रेष्ठ प्रक्रियाओं के सतत प्रसार के जरिये लगातार सीखने को संभव बनाएगा।

रॉबिन हुड इंडेक्स

क्या हो अगर किसी देश के सबसे अमीर व्यक्ति को उस देश की सरकार का सारा खर्च उठाना पड़े? कितने दिन तक दुनियाभर के धनकुबेर अपने देश की सरकारों का खर्च उठा पाएंगे, यह जानने के लिए ब्लूमबर्ग ने 2018 रॉबिन हुड इंडेक्स बनाया है। इस इंडेक्स में कुल 49 देशों को शामिल किया गया है। इस इंडेक्स को तैयार करने में विभिन्न देशों की अलग अलग तरह की सरकारों, उनके विभिन्न खर्चों और उस देश के सबसे अमीर व्यक्ति को शामिल किया गया है। इस इंडेक्स में दिसंबर 2017 के अंत में देश के सबसे बड़े व्यक्ति की संपत्ति और उस देश की सरकार को चलाने के लिए किए जाने वाले रोजाना खर्च की तुलना की गई है। आपको बता दें कि 49 में से महज 4 देश ऐसे हैं जहां कि सबसे अमीर शख्सियत एक महिला हैं। इनमें अंगोला, ऑस्ट्रेलिया, चिली और नीदरलैंड शामिल हैं।

क्या है

1. इंडेक्स को तैयार करते समय यह माना गया है कि अगर किसी देश की सरकार के पास अगर संसाधन खत्म हो जाएं और उस देश के सबसे अमीर व्यक्ति की सभी सम्पत्तियों को बेचकर वह राशि सरकार को दान दे दी जाए तो यह राशि कितने दिन तक सरकार के दफ्तर और एजेंसियों में काम-काज ठप्प होने या ताला लगने से रोक सकती है।
2. इस इंडेक्स को तैयार करने में दो अहम आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। पहला ब्लूमबर्ग का बिलेनायर्स इंडेक्स और दूसरा सरकार के खर्च पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान।
3. भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी कुल 20 दिन तक भारत की सरकार का खर्च उठा सकते हैं। आपको बता दें कि अनुमान के मुताबिक भारत सरकार का रोजाना कुल खर्च 198.72 करोड़ डॉलर है।
4. जबकि मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 4030 करोड़ डॉलर की है। जीडीपी की तुलना में भारत सरकार का खर्च 27.3 फीसद के बराबर है।
5. सायप्रस के सबसे धनी व्यक्ति जॉहन फ्रेडरिकसन अपने देश की सरकार को 441 दिनों तक चला सकते हैं। 2018 में सरकार के अनुमानित खर्चे 2.36 करोड़ डॉलर है। देश की जनसंख्या कम होने के कारण सरकारी स्कीम का खर्च कम है।
6. साथ ही देश की इकोनॉमी टूरिज्म और सेवाओं पर आधारित है। सायप्रस सरकार के खर्च फ्रेडरिकसन की कुल 1000 करोड़ डॉलर की संपत्ति से सबसे लंबे समय तक चल सकता है।
7. जैक मां 4 तो जेफ बेजॉय 5 दिन उठा सकते हैं सरकार का खर्च
8. इसकी तुलना में सबसे ज्यादा खर्च जिन देशों की सरकार का है उनमें जापान, पोलैंड, अमेरिका और चीन शामिल हैं। जैक मां जो दुनिया के 16वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं।
9. चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को महज चार दिन तक चला सकते हैं। आपको बता दें की जैक मां की कुल संपत्ति 4780 करोड़ डॉलर की है। जेफ बेजॉय भी इससे बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। जेफ बेजॉय की 9900 करोड़ डॉलर की सम्पत्ति अमेरिका की सरकार का खर्च महज 5 दिन तक उठा सकती है।

भारत के वन्य क्षेत्र में 1 प्रतिशत का इजाफा

पिछले दो साल में भारत के वन क्षेत्र में एक फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। यह 2015 के 7, 01,495 वर्ग किलोमीटर से 2017 में बढ़कर 7,08,273 वर्ग किलोमीटर हो गया है। यानी कुल वनक्षेत्र में 6,778 वर्ग किलोमीटर का इजाफा हुआ है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, ओडिशा और तेलंगाना में वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा बढ़त हुई है। इस मामूली इजाफे के बाद देश का वन क्षेत्र कुल क्षेत्रफल के 21.54 फीसदी तक पहुंच गया है। पर्यावरण मंत्रालय ने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2017 जारी करते हुए यह जानकारी दी। इस रिपोर्ट में यह सामने आया कि देश में कुल वन और वृक्ष क्षेत्र बढ़कर 8,02,088 वर्ग किलोमीटर हो गया है। यह कुल 8,021 वर्ग किलोमीटर की बढ़त है। वर्ष 2015 के आकलन के अनुपात में यह कुल 1 फीसदी का इजाफा है। अब देश के कुल 24.39 प्रतिशत भू-क्षेत्रफल पर वन और वृक्ष क्षेत्र है। पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि 2015 के मुकाबले 2017 में अत्यंत सघन वनों का क्षेत्रफल 1.36 प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने कहा कि यह अच्छी खबर है क्योंकि वेरी डेंस फॉरेस्ट (वीडीएफ) वातावरण से सबसे ज्यादा कार्बन अवशोषित करते हैं।

क्या है

1. 2017 की मूल्यांकन रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि करीब 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 33 फीसदी से ज्यादा इलाका वन क्षेत्र में आता है।
2. इनमें से सात केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों- मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और मणिपुर में 75 प्रतिशत इलाका वन्य क्षेत्र है। वहीं 8 राज्यों- त्रिपुरा, गोवा, सिक्किम, केरल और उत्तराखंड, दादर और नगर हवेली, छत्तीसगढ़ और असम में 33-75 प्रतिशत इलाका वन्य क्षेत्र है।
3. रिपोर्ट में सामने आया है कि पांच उत्तर-पूर्वी राज्यों- मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय में 2015 के मुकाबले 2017 में वन्य क्षेत्र में गिरावट हुई है।
4. दिल्ली स्थित सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ने इस रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'यह देखना अच्छी बात है कि अत्यंत सघन वनों के क्षेत्रफलों में इजाफा हुआ है। हालांकि इसके पीछे की वजह 2015 के मुकाबले इस बार अधिक जिलों को आकलन में शामिल करना हो सकता है।'
5. सीएसई ने कहा कि 2015 के पिछले मूल्यांकन में 589 जिलों को शामिल किया गया था जबकि इस बार 633 जिलों को शामिल किया गया है।

किराए की कोख से मां बनने पर भी मिलेगा मातृत्व अवकाश

कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि किराए की कोख से बच्चा प्राप्त करने वाली केंद्र सरकार की कर्मचारियों को भी मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा। ये महिला कर्मचारी वेतन सहित 26 सप्ताह (लगभग 180 दिन) का मातृत्व अवकाश प्राप्त कर सकती हैं।

क्या है

1. कार्मिक मंत्रालय ने इस मुद्दे पर 2015 में आए दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बारे में केंद्र सरकार के सभी विभागों को पत्र लिखा है। मंत्रालय ने इसके साथ अदालत के आदेश की प्रति भी संलग्न की है।
2. अदालत का फैसला केंद्रीय विद्यालय की एक शिक्षिका की याचिका पर आया था, जिन्होंने किराए की कोख से जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था।
3. उन्हें इस आधार पर मातृत्व अवकाश नहीं दिया गया था कि वह जैविक मां नहीं हैं। लेकिन, हाई कोर्ट ने कहा था कि बच्चा हासिल करने वाली मां भी मातृत्व अवकाश की हकदार होगी।

4. सक्षम प्राधिकारी किराए की कोख से बच्चा हासिल करने वाली मां को मातृत्व अवकाश देने के समय और अवधि के बारे में फैसला करेंगे।

एशिया का पहला करोड़पति गांव

अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिला स्थित बमजा गांव एशिया के सर्वाधिक धनी गांवों की लिस्ट में शामिल हो गया है। दरअसल भारतीय आर्मी द्वारा तवांग गैरीसन की प्रमुख स्थान योजना इकाइयों के लिए किया गया है। इसके एवज में यहां के जमीन के मालिकों को रक्षा मंत्रालय की ओर से अच्छी-खासी रकम दी गयी है। कुल 200.056 एकड़ जमीन अधिग्रहण के एवज में गांव के 31 परिवारों को रक्षा मंत्रालय की ओर से 40.8 करोड़ रुपये का चेक सौंपा गया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लाभार्थियों को यह सम्मान सौंपा।

क्या है

1. 31 में से प्रत्येक 29 परिवार को 1.09 करोड़ रुपये का चेक दिया गया जबकि उनमें से एक को 2.45 करोड़ रुपये और दूसरे को 6.73 करोड़ की रकम दी गयी।
2. अब गांव का प्रत्येक परिवार करोड़पति है। बमजा संभवतः भारत का एकमात्र गांव है जहां का हर परिवार करोड़पति है। यह जमीन भारतीय सेना द्वारा अधिग्रहित किया गया है।

भारत का रक्षा बजट दुनिया के शीर्ष पांच में शामिल

ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए भारत का रक्षा बजट पहली बार दुनिया के शीर्ष पांच बजट में शामिल हो गया है। लंदन स्थित एक वैश्विक विचार समूह ने अपनी एक नई रिपोर्ट में यह कहा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज (आईआईएसएस) की मिलिट्री बैलेंस 2018 रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2017 में 52.5 अरब डॉलर के खर्च के साथ रक्षा बजट के मामले में ब्रिटेन को पीछे छोड़कर पांचवे स्थान पर पहुंच गया। इससे पहले वर्ष 2016 में रक्षा बजट 51.1 अरब डॉलर था। इसके उलट, 2016 में ब्रिटेन का रक्षा बजट (52.5 अरब डॉलर) से घटकर पिछले साल 50.7 अरब डॉलर रह गया।

क्या है

1. आईआईएसएस के दक्षिण एशिया के सीनियर फ़ैलो राहुल रॉय चौधरी ने कहा कि यह भारत और ब्रिटेन के बीच सैन्य संतुलन में महत्वपूर्ण बदलाव को दिखाता है।
2. वैश्विक संदर्भ में भारत, ब्रिटेन की तुलना में अपने क्षेत्रीय संसाधनों को विकसित करने के लिए ज्यादा राशि आवंटित कर रहा है। भारत अपनी सैन्य क्षमता का आधुनिकीकरण कर रहा है।
3. रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बजट के साथ चीन भारत के रक्षा बजट से तीन गुना (150.5 अरब डॉलर) खर्च कर रहा है।
4. चीन का वास्तविक रक्षा बजट 2016-17 में तकरीबन 25 प्रतिशत बढ़ा, जबकि इस दौरान भारत का बजट महज 2.4 प्रतिशत बढ़ा ।
5. राय चौधरी ने कहा कि डोकलाम के बाद चीन के साथ भारतीय सैन्य संतुलन महत्वपूर्ण रूप से चीन के पक्ष में है।
6. वर्ष 2000 के बाद चीन ने जापान, दक्षिण कोरिया और भारत को मिलाकर ज्यादा पनडुब्बी, विध्वंसक पोतों, लड़ाकू विमानों का निर्माण किया। क्षेत्रीय सैन्य दृष्टि से चीन का दबदबा बना रहेगा और क्षेत्र में अमेरिका को भी चुनौती देगा।

पृथ्वी-2 मिसाइल का सफल परीक्षण

भारत ने देश में निर्मित एवं परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का ओडिशा में एक परीक्षण रेंज से सफल प्रायोगिक परीक्षण किया। सेना ने इस्तेमाल के दौरान इसका परीक्षण किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सतह से सतह पर मार करने में सक्षम और 350 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली इस मिसाइल का परीक्षण सुबह

करीब नौ बजकर 50 मिनट पर यहां निकट स्थित चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) के परिसर तीन से मोबाइल लॉन्चर के माध्यम से किया गया।

क्या है

1. इस अत्याधुनिक मिसाइल का परीक्षण सफल रहा और मिशन के लक्ष्य पूरे हुए। पृथ्वी-2 मिसाइल 500 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम वजनी आयुध ले जाने में सक्षम है और यह दो तरल प्रणोदन इंजनों से संचालित होती है। यह अपने लक्ष्य को सटीकता से निशाना बनाने के लिए अत्याधुनिक प्रणाली का इस्तेमाल करती है।
2. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के एक वैज्ञानिक ने कहा कि इस अत्याधुनिक मिसाइल को परीक्षण के लिए उत्पादन भंडार से चुना गया और यह परीक्षण गतिविधियां विशेष रूप से गठित सामरिक बल कमान (एसएफसी) ने की और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इस पर नजर रखी।
3. मिसाइल के प्रक्षेपण पथ पर ओडिशा के तट के निकट स्थित टेलीमेट्री स्टेशनों, डीआरडीओ रडारों और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम्स ने नजर रखी। बंगाल की खाड़ी में निर्धारित प्रभाव बिंदु के निकट तैनात पोत पर सवार टीम ने टर्मिनल गतिविधियों एवं मिसाइल के समुद्र में उतरने की निगरानी की।
4. इससे पहले 21 नवंबर 2016 को इसी जगह से दो पृथ्वी 2 मिसाइलों का एक के बाद एक परीक्षण किया गया था।
5. इस नौ मीटर लंबी मिसाइल को वर्ष 2003 में भारतीय सशस्त्र बल में शामिल किया गया था। यह पहली ऐसी मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित किया है।

15 लाख साल पुरानी सभ्यता के प्रमाण

अम्बुज माहेश्वरी, रायसेन जिला मुख्यालय से 18 किमी दूर ग्राम नरवर के पास टिकोदा व डामडोंगरी में 15 लाख वर्ष पुराने प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यह जानकारी खुद पुरातत्व आयुक्त अनुपम राजन ने दी है। उन्होंने बताया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली के सेवानिवृत्त महानिदेशक डॉ.एसवी ओटा द्वारा इस क्षेत्र में वर्ष 2010 से 2015 तक लगातार 6 साल तक कराए गए उत्खनन से यह प्रमाणिक तथ्य प्रकाश में आए हैं।

क्या है

1. श्री राजन ने इस क्षेत्र में पुरातत्वीय एवं ऐतिहासिक प्रमाणिक तथ्य की जानकारी देते हुए बताया टिकोदा स्थल के निचले स्तरों से जो पाषाण उपकरण मिले हैं उनकी समानता अफ्रीका से प्राप्त ओल्डवान संस्कृति के उपकरणों से मिलती-जुलती है।
2. इन दोनों क्षेत्रों में प्राचीन मानव जिस जलवायु में रहता था, उसके रहन-सहन, खान-पान समेत अन्य गतिविधियों की जानकारी, मिट्टी के नमूनों और पाषाण उपकरणों से मिलती है। इस उत्खनन कार्य में शतुरमुर्ग के अण्डे के टुकड़े भी मिले हैं।
3. मानव निर्मित पाषाण औजारों में हस्त-कुठार, विदारणी, खुचरनी एवं अन्य फलक उपकरण प्रमुख हैं। इन स्थलों का प्रागैतिहासिक कालीन प्रभाव विभिन्न उत्खनित भागों में लगभग एक मीटर से 9.5 मीटर तक अलग-अलग पाया गया है। यह सभी पुरातत्विक साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह क्षेत्र लाखों वर्ष पहले मानव गतिविधियों का केन्द्र रहा है।
4. यहाँ मिले पाषाण उपकरण अफ्रीका के ओल्डोवन कल्चर से मिलते जुलते हैं। अफ्रीका के इस कल्चर में प्रागैतिहासिक काल में सबसे प्रारंभिक और व्यापक पुरातत्वीय उपकरण माने गए हैं।
5. अफ्रीका में यह 3.3 लाख साल पहले के माने गए हैं और यह लोमेकवियन टूल भी कहे जाते हैं। यह अब तक अफ्रीका, दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप के बहुत से प्राचीन घरों में मिले हैं।

अन्तरराष्ट्रीय

दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट ने भरी उड़ान

अमेरिका में फॉल्कन हेवी रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। यह रॉकेट दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट माना जाता है। अमरीका के फ्लोरिडा राज्य में स्थित कैंनेडी स्पेस सेंटर से नासा के ऐतिहासिक लॉन्च पैड से 7 फरवरी 2018 को दुनिया के इस सबसे शक्तिशाली रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। फॉल्कन हेवी रॉकेट को अमरीकी व्यवसायी इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने लॉन्च किया। मौजूदा वक्त में बाकी रॉकेट अपने साथ जितना भार ले जा सकते हैं, फॉल्कन हेवी उससे दोगुना भार को ले जाने की क्षमता रखता है। स्पेस एक्स के सीईओ की मानें तो इस रॉकेट की पहली उड़ान की सफलता 50 प्रतिशत थी लेकिन यह सफलतापूर्वक लॉन्च होने में सफल हो गया।

फॉल्कन हेवी की खूबियां

1. फॉल्कन हेवी की खास बात यह है कि इस रॉकेट के साथ एलन मस्क की स्पार्टस कार को भी भेजा गया है।
2. फॉल्कन हेवी रॉकेट का वजन लगभग 63.8 टन है, जो दो स्पेस शटल के वजन के बराबर होता है।
3. इस रॉकेट में 27 मर्लिन इंजन लगे हैं और इसकी लम्बाई 230 फुट है।
4. रॉकेट के लांच होने के बाद स्पेसएक्स के कमेंटेटर लॉरेन लियोन्स ने कहा, 'वाह, क्या तुम लोगों ने देखा? यह बहुत बढ़िया था।

स्पेस एक्स

1. इससे पहले इस रॉकेट लांच के संबंध में स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने कहा था कि पूरी दुनिया से लोग सबसे बड़े रॉकेट और आतिशबाजी के प्रदर्शन को देखने के यहां लिए पहुंच रहे हैं करीब पचास साल पहले जिस पैड से मानव का चांद्र पर जाने का सफर शुरू हुआ, उसमें स्पेसएक्स ने अपने फाल्कन 9 और फाल्कन हेवी रॉकेटों के अनुकूल बदलाव लाया है।
2. मस्क ने इससे पहले ट्वीट करके कहा था कि "केप कनेडी स्थित अपोलो लांचपैड 39 ए से छह फरवरी को फाल्कन हेवी की पहली उड़ान का लक्ष्य है।"
3. दुनिया के इस सबसे शक्तिशाली रॉकेट को टेस्ला के बिलेनियर एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने निर्मित किया है। इससे पहले इस कंपनी ने इससे पहले सफलतापूर्वक रॉकेट बूस्टर्स का इस्तेमाल किया था। भविष्य में इस रॉकेट के जरिए लोगों को मंगल और चांद्र पर भेजा जा सकेगा।

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 14 फरवरी 2018 को देश के नाम टेलिविजन पर प्रसारित संबोधन में इस्तीफे का ऐलान किया। इसके पहले जुमा की पार्टी एएनसी ने उन्हें पद छोड़ने या फिर 15 फरवरी 2018 को संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने को कहा था। 75 वर्षीय जुमा पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा था। उन्हें उपराष्ट्रपति सिरिल रामापोसा के लिए जगह खाली करने को कहा जा रहा था। साल 2009 से सत्ता में रहे जुमा पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं।

क्या है

1. गौरतलब है कि राष्ट्रपति जैकब जुमा से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में दक्षिण अफ्रीकी पुलिस ने उनके नजदीकी गुप्ता परिवार के भव्य आवास परिसर में छाप मारा।
2. सत्तारूढ़ अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस (एएनसी) ने जुमा पर राष्ट्रपति पद छोड़ने के लिए दबाव बढ़ा दिया था। पार्टी ने कहा है कि इस्तीफा न देने पर जुमा के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। धमकियों के बावजूद निडर जुमा ने बुधवार को इस्तीफा देने से इन्कार कर दिया था।

3. गुप्ता परिवार के चार भाइयों के आवास पर छापे में पुलिस ने कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं। **भारतीय मूल के इस परिवार पर जुमा के साथ मिलकर आर्थिक अनियमितता का आरोप है।**
4. गुप्ता परिवार के आलीशान आवास पर छापामारी के बाद पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन गिरफ्तार लोगों में गुप्ता बंधुओं में से कोई नहीं था। गुप्ता परिवार के वकील ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मीडिया ने गलत सूचना दी है। वह नहीं बता सकते कि किसे गिरफ्तार किया गया है।
5. **सन 1993 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से दक्षिण अफ्रीका गए अतुल गुप्ता, अजय गुप्ता, राजेश गुप्ता और वरुण गुप्ता कुछ ही वर्षों में वहां के कारोबार जगत में इस तरह छा गए कि सत्ता के शीर्ष तक उनकी तूती बोलने लगी।**
6. 2003 में उनके संबंध तत्कालीन उप राष्ट्रपति जैकब जुमा से बने तो वे बढ़ते चले गए। यहां तक कि जुमा के बेटे और बेटी गुप्ता बंधुओं की कंपनियों में बतौर निदेशक भी नियुक्त हुए। 2009 में हुए आम चुनाव में गुप्ता बंधुओं ने जुमा का भरपूर साथ दिया। जुमा राष्ट्रपति बने तो उसका लाभ भी परिवार को मिला। इसके बाद परिवार का रुतबा बढ़ता गया।
7. खनन, अचल संपत्ति, कंप्यूटर, मीडिया आदि के कारोबार में परिवार का दखल बढ़ता गया। मौजूदा समय में परिवार की संपत्ति पांच हजार करोड़ से ज्यादा की मानी जाती है। विवाद तब पैदा हुआ जब सन 2013 में बंधुओं के भारतीय रिश्तेदारों को लेकर गया चार्टर्ड प्लेन दक्षिण अफ्रीका के वायुसेना अड्डे पर उतरा।
8. इससे सत्तारूढ़ दल की खासी छीछालेदर हुई और गुप्ता बंधुओं के खिलाफ विरोध मुखर हो गया। इसी के बाद जुमा विरोधियों ने एकजुट होकर गुप्ता बंधुओं को घेरना शुरू किया।

चीन का पहला जॉइंट एजुकेशन सैटलाइट लॉन्च

चीन ने अपना पहला साझा शिक्षा उपग्रह लांच किया। उपग्रह को लॉन्ग मार्च-2डी रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में छोड़ा गया। यह उपग्रह स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के साथ अपना डेटा साझा करेगा। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, तीन किलोग्राम का क्यूबसैटलाइट यंग पायनियर-1 ने धरती से 502 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में प्रवेश किया।

क्या है

1. रॉकेट अपने साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सैटलाइट झागहेंग-1 और पांच अन्य छोटे-छोटे उपग्रह भी लेकर गया है, जिनके जरिए भूकंप के आंकड़ों का अध्ययन किया जाएगा।
2. उपग्रह निर्माता कामसैट के संस्थापक व सीईओ शी ताओ ने बताया कि पायनियर-1 से वायरलेस स्टोरेज व यूवी आवृत्ति पर रेडियो तरंगों का प्रेषण संभव हो जाएगा।
3. उपग्रह प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के विद्यालयों व अन्य शिक्षण संस्थानों के साथ अपना डेटा साझा करेगा।

चीन ने किया मिसाइल रोधक प्रणाली का परीक्षण

चीन ने एक और मिसाइल रोधक प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए इसे अपनी रक्षा के लिए उठाया गया कदम बताते हुए कहा कि यह परीक्षण किसी देश को लक्ष्य करके नहीं किया गया। चीनी राष्ट्रपति शी जिंपिंग की निगरानी में शुरू हुए महत्वाकांक्षी आधुनिकीकरण योजना के सभी प्रकार के मिसाइलों पर अनुसंधान का काम तेज हो गया है जिनमें अंतरिक्ष स्थित सैटलाइटों से लेकर अत्याधुनिक परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं।

क्या है

1. चीन की सीमाओं के भीतर जमीन से मिडकोर्स मिसाइल रोधक तकनीक का परीक्षण किया गया। यह परीक्षण अपने संभावित लक्ष्य तक सफलतापूर्वक पहुंची। यह रक्षा में था और किसी देश को निशाना बनाने के इरादे से नहीं किया गया था। वक्तव्य में और कोई जानकारी नहीं दी गयी है।

2. गौरतलब है कि चीन अपने सहयोगी रुस के साथ दक्षिण कोरिया में अमेरिका की ओर से मिसाइल रोधक टर्मिनल हाई एल्टीच्यूड एरिया डिफेंस (थाड) की तैनाती का विरोध करता रहा है।
3. हालांकि इस तकनीक में अनुसंधान करने से चीन पर भी कोई रोक नहीं है। चीन और रुस ने हाल ही में गत वर्ष मिसाइल रोधक संयुक्त अभ्यास भी किया था।

नए छोटे परमाणु बम विकसित करेगा अमेरिका

अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को आधुनिक करने की नई नीति की घोषणा की है। वह नए छोटे परमाणु बम विकसित करेगा और देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा। अमेरिकी प्रेजिडेंट डॉनल्ड ट्रंप ने कहा कि यह पॉलिसी 21वीं सदी में सामने आ रहे विभिन्न खतरों का सामना करने के अनुरूप तैयार की गई है।

क्या है

1. पेंटागन में 2018 न्यूक्लियर पॉस्चर रिव्यू (एनपीआर) के जारी होने के बाद ट्रंप ने कहा, 'नई पॉलिसी शस्त्र नियंत्रण और परमाणु अप्रसार की भी हमारी प्रतिबद्धता को दोहराती है।
2. इसके साथ ही यह परमाणु परीक्षणों पर रोक बनाए रखता है और परमाणु आतंकवाद को रोकने, पता लगाने और उसपर प्रतिक्रिया देने के प्रयासों में सुधार के लिए भी प्रतिबद्ध है।'
3. एनपीआर 100 पेज की है और इसकी प्रस्तावना में रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने कहा है कि एक प्रभावी परमाणु प्रतिरोध बनाए रखना युद्ध लड़ने की तुलना में कम महंगा है।

विदेशी धरती पर भारतीय सेना ने किया था पहला ऑपरेशन

मालदीव में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच वहां की विपक्षी पार्टी ने भारत से इसे मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। इसके बाद भारत ने इस मामले पर कहा कि वह मालदीव में आपातकाल लगाए जाने से चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की गिरफ्तारी और राजनीतिक आंकड़े चिंता का कारण हैं। सरकार सावधानीपूर्वक पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। भारत इस संबंध में क्या कदम उठाने जा रहा है, यह तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन भारत ने 1988 में मालदीव की सैन्य मदद की थी। आजादी के बाद विदेशी धरती पर भारत की पहली सैन्य कार्रवाई 'ऑपरेशन कैक्टस' के नाम से आज भी इतिहास के पन्नों पर दर्ज है।

क्या है

1. नवंबर 1988 में 'तमिल इलम के पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन' (प्लोटे) तमिल उग्रवादियों ने मालदीव पर हमला किया। भारतीय खुफिया एजेंसी राॅ की सूचना पर और उसकी मदद से भारतीय सशस्त्र बल ने उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए एक सैन्य अभियान की शुरुआत की।
2. इस ऑपरेशन को ऑपरेशन कैक्टस के नाम से जाना गया। 3 नवंबर, 1988 की रात को भारतीय वायुसेना की आगरा पैराशूट रेजिमेंट की छठी बटालियन ने मालदीव से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरी।
3. इस टुकड़ी ने हुलहुल में लैंड किया और माले में घंटे भर के भीतर तब के राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम की सरकार को बहाल कर दिया। सेना की ओर से किए गए इस तीव्र अभियान और राॅ की सटीक खुफिया जानकारी के जरिए उग्रवादियों का दमन किया जा सका।

क्या हुआ था 3 नवंबर 1988 को मालदीव में?

1. 3 नवंबर 1988 में श्रीलंकाई उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम (PLOTE) के हथियारबंद उग्रवादी मालदीव पहुंचे। स्पीडबोट्स के जरिए मालदीव पहुंचे उग्रवादी पर्यटकों के भेष में थे।
2. दरअसल यह योजना मालदीव में तख्तापलट की थी। श्रीलंका में कारोबार करने वाले मालदीव के अब्दुल्लाह लथुफी ने उग्रवादियों के साथ मिलकर इस योजना का खाका खींचा था।

3. पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसीर पर भी इस साजिश में शामिल होने का आरोप था। अब श्रीलंका में बनाई गई इस प्लानिंग को अब मालदीव में अंजाम दिया जाना था।

हरकत में आए राजीव गांधी

1. 3 नवंबर को मालदीव पहुंचे हथियारबंद उग्रवादियों ने मालदीव की राजधानी माले की ज्यादातर सरकारी बिल्डिंगों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। सरकारी बिल्डिंगों के साथ एयरपोर्ट, बंदरगाह और टेलिविजन स्टेशन भी उग्रवादियों के नियंत्रण में चले गए।
2. उग्रवादियों का मकसद तत्कालीन राष्ट्रपति मामून अब्दुल गय्यूम तक पहुंचना था। राष्ट्रपति को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने भारत समेत कई देशों को इमरजेंसी संदेश भेजा।
3. भारत को संदेश मिलने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को इस बारे में सभी सूचना दी गई। राजीव गांधी ने बगैर वक्त गंवाए इस पर एक्शन का मन बना लिया।

तब हुई सैन्य कार्रवाई

1. 3 नवंबर की रात को ही आगरा छावनी से भारतीय सेना की पैराशूट ब्रिगेड के करीब 300 जवान माले के लिए रवाना हुए।
2. राष्ट्रपति गय्यूम की अपील के महज नौ घंटे के भीतर ही भारतीय सेना नॉन स्टॉप उड़ान भरते हुए हुलहुले एयरपोर्ट पर पहुंची। यह एयरपोर्ट माले की सेना के नियंत्रण में था।
3. हुलहुले से लगनों को पार करते हुए भारतीय टुकड़ी राजधानी माले पहुंची। इस बीच कोच्चि से भारत ने और सेना भेजी। माले के ऊपर भारतीय वायुसेना के मिराज विमान उड़ान भरने लगे।
4. उग्रवादियों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्हें इतनी जल्दी जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इससे उग्रवादियों का मनोबल पूरी तरह हिल गया।
5. भारतीय सेना ने सबसे पहले एयरपोर्ट को अपने कब्जे में लिया और राष्ट्रपति गय्यूम को सुरक्षित किया। जमीनी और हवाई कार्रवाई के बाद भारतीय नौसेना के युद्धपोत गोदावरी और बेतवा भी हरकत में आ चुके थे। उन्होंने माले और श्रीलंका के बीच उग्रवादियों की सप्लाई लाइन काट दी।

नेपाल के 41वें पीएम ली शपथ

नेपाल के ऐतिहासिक संसदीय चुनावों में वामपंथी गठबंधन की बड़ी जीत के बाद सीपीएन-यूएमएल के अध्यक्ष के. पी. शर्मा ओली दूसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए। ओली के प्रधानमंत्री बनने से नेपाल में राजनीतिक स्थिरता की उम्मीदें एक बार फिर से जगी हैं। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 65 साल के ओली को देश का 41वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया। चीन समर्थक रुख के लिए प्रसिद्ध ओली इससे पहले 11 अक्तूबर, 2015 से तीन अगस्त, 2016 तक नेपाल के प्रधानमंत्री रहे हैं।

क्या है

1. नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत ओली को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इस अनुच्छेद के मुताबिक, जब प्रतिनिधि सभा में किसी पार्टी का स्पष्ट बहुमत नहीं हो तो राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा के ऐसे सदस्य को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे जिसे दो या इससे अधिक राजनीतिक पार्टियों के समर्थन से बहुमत प्राप्त हो सके।
2. प्रधानमंत्री पद के लिए ओली का समर्थन यूसीपीएन-माओवादी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी नेपाल और मधेशी राइट्स फोरम डेमोक्रेटिक के अलावा 13 अन्य छोटी पार्टियों ने किया है। इससे पहले, नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने राष्ट्र को संबोधित किया और प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया।
3. गौरतलब है कि देश में हुए ऐतिहासिक संसदीय और स्थानीय चुनावों में पार्टी की बुरी हार के करीब दो महीने बाद देउबा ने इस्तीफा दिया है।

4. देउबा सीपीएन (माओवादी सेन्टर) के समर्थन से पिछले वर्ष छह जून को नेपाल के 40वें प्रधानमंत्री बने थे। सीपीएन (माओवादी सेन्टर) अब वामपंथी गठबंधन का हिस्सा हैं और सीपीएन-यूएमएल के साथ विलय कर रहा है। टेलीविजन प्रसारण के दौरान देउबा ने कहा, “मेरे नेतृत्व में सरकार के तीनों स्तरों के लिए मतदान सफलतापूर्वक पूरा हुआ, जिससे सत्ता हस्तांतरण की नींव पड़ी”।
5. सीपीएन-यूएमएल और सीपीएन-माओवादी सेन्टर गठबंधन को दिसंबर में हुए आम चुनावों में 275 में से 174 सीटों पर जीत मिली। सीपीएन-यूएमएल का नेतृत्व ओली जबकि सीपीएन-माओवादी सेन्टर का नेतृत्व पुष्प कुमार दहल ‘प्रचंड’ करते हैं।
6. ओली की पार्टी सीपीएन-यूएमएल को 121 सीटें मिली और वह संसद में सबसे बड़ी पार्टी बनी। नेपाली कांग्रेस को 63 सीटें मिली हैं जबकि सीपीएन-माओवादी सेन्टर के पास 53 सीटें हैं। सीपीएन-यूएमएल और सीपीएन-माओवादी सेन्टर की कुल सीटें 174 हैं। बहुमत की सरकार बनाने के लिए यह पर्याप्त आंकड़ा है। मधेसी पार्टियां, राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल को 17 और फेडरल सोशलिस्ट पार्टी नेपाल को 16 सीटें मिली हैं।

दुबई में दुनिया का सबसे ऊंचा होटल

दुनिया में सबसे ऊंचा होटल 12 फरवरी 2018 दुबई में खुलने जा रहा है। सोने की चमक वाले 75 मंजिला गेवोरा होटल की ऊंचाई 356 मीटर है। खास बात यह है कि इससे पहले भी रिकॉर्ड दुबई के ही नाम था।

पूर्व रिकॉर्डधारी जेडब्ल्यू मैरिएट मार्किंस की ऊंचाई एक मीटर कम है। दुबई पूरी दुनिया में अपनी ऊंची इमारतों के लिए अक्सर चर्चा में रहता है।

क्या है

1. दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी दुबई में ही है।
2. गेवोरा होटल पेरिस के एफिल टावर से भी 56 मीटर ऊंचा है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक गेवोरा सोमवार से मेहमानों का स्वागत करेगा।
3. गेवोरा होटल में 528 कमरे हैं। हालांकि ऊंचाई में दूसरे नंबर पर खिसकने वाले मार्किंस होटल में 1608 कमरे हैं।
4. होटल में चार रेस्टोरेंट, ओपन एयर पूल और हेल्थ क्लब भी हैं। इसके अलावा 71वीं मंजिल पर स्पा भी है।

अर्थशास्त्र

बजट 2018

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने 1 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया का बजट पेश किया। बजट भाषण में लोकलुभावन घोषणाओं की बजाय किसानों, गरीबों, गृहणियों से लेकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को सौगात मिली। जबकि आयकर में कोई बदलाव नहीं करते हुए वेतनभोगी करदाता को 40,000 रुपये की मानक कटौती का लाभ देने का प्रस्ताव किया। साथ ही पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी लाने के लिए शुल्क में दो-दो रुपये की कमी लाई गई। बजट भाषण में वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि सन् 2022 तक देश के हरेक गरीब के पास अपना घर होगा। बजट में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को गृहऋण में भी राहत देने की घोषणा की गई। जबकि खेती का बाजार मजबूत करने के लिए 2000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वित्तमंत्री अरूण जेटली ने किसानों के लिए कर्ज की राशि 11 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की है और कृषि सिंचाई योजना के लिए 2600 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा देश के हरेक गरीब को 5 लाख तक का नगद मेडिकल सुविधा का लाभ उठाने का प्रस्ताव किया गया। इससे देश के 40 फीसदी लोगों को फायदा होगा और 10 करोड़ परिवार सीधे तौर पर उपचार का फायदा ले सकेंगे। इससे इतर टीबी रोगियों को पोषण के लिए 500 रुपये प्रतिमाह सरकार द्वारा मुहैया कराए जाएंगे। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया का बजट पेश किया। बजट भाषण में लोकलुभावन घोषणाओं की बजाय किसानों, गरीबों,

गृहणियों से लेकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को सौगात मिली। जबकि आयकर में कोई बदलाव नहीं करते हुए वेतनभोगी करदाता को 40,000 रुपये की मानक कटौती का लाभ देने का प्रस्ताव किया।

बजट की मुख्य विशेषताएं

1. वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था 2.5 ट्रिलियन अमरीकी डालर की है
2. वर्ष 2018-19 के लिए सकल घरेलू उत्पाद 7.4% देखा जा रहा है
3. विकास दर में 8% से 15% तक की वृद्धि
4. 250 करोड़ रुपये तक के एमएसईएम के कारोबार पर टैक्स स्लैब 25%
5. इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं
6. वेतनभोगी करदाताओं को 40000 रुपये की मानक कटौती
7. सीनियर नागरिकों के लिए मेडीक्लेम सीमाएं रु 30000 से 50000 तक बढ़ी
8. फिशरीज और एग्रीकल्चर के लिए 10000 करोड़ रुपये आवंटन
9. निर्यात 15% बढ़ेगा
10. 2022 तक किसानों की आय होगी डबल
11. खरीफ फसलों के लिए एमएसपी 1.5 होगा
12. शहरी क्षेत्रों में सस्ते घरों के लिए 51 लाख और ग्रामीण इलाकों में 37 लाख सहायता
13. 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाएंगे
14. 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (5 लाख मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल केंद्र)
15. आरआईएसई के लिए 1000 करोड़ रुपये का आवंटन
16. एमएसएमई के ऋण सहायता के लिए 3,794 करोड़ रुपये का आवंटन
17. अगले वित्त वर्ष में 3 लाख करोड़ रुपये के मुद्रा ऋण का लक्ष्य
18. 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना होगी
19. कपड़ा क्षेत्र के लिए 7148 करोड़ रुपये का आवंटन
20. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए 1400 करोड़ रुपये का आवंटन
21. वर्ष के अंत तक 9000 किलोमीटर का राजमार्ग निर्माण लक्ष्य
22. रेलवे को 1.48 लाख करोड़ रुपये का आवंटन
23. बेंगलुरु मेट्रो नेटवर्क के लिए 17000 करोड़ का आवंटन
24. मुंबई रेलवे को 11000 करोड़ का आवंटन
25. स्मार्ट सिटी के लिए 2.04 लाख करोड़ रुपये की योजना
26. क्रिप्टो करेंसी का कोई वजूद नहीं
27. डिजिटल भारत के लिए 373 करोड़ रुपये का आवंटन
28. इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5.97 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च का प्रस्ताव

इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

इनकम टैक्स स्लैब (60 साल तक की उम्र वालों के लिए)

| आय | मौजूदा दर |
|-------------------|-----------|
| 0 से 2.5 लाख रुपए | 0% |
| 2.5 लाख से 5 लाख | 5% |
| 5 लाख से 10 लाख | 20% |
| 10 लाख से ऊपर | 30% |

टैक्स में छूट

3.5 लाख रुपए तक की आय पर 2500 की छूट 87 ए के तहत मिलती है। मतलब आपके कुल टैक्स में से

2500 रुपए घट जाते हैं। इस कारण 3 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री हो जाती है।

सरचार्ज

50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की आय पर 10 फीसदी सरचार्ज

1 करोड़ रुपए से ऊपर की आय पर 15 फीसदी सरचार्ज

सेस

कुल आयकर पर 3 फीसदी सेस और साथ में सरचार्ज

इनकम टैक्स स्लैब (60 साल से ज्यादा और 80 साल से कम)

| आय | मौजूदा दर |
|-----------------|-----------|
| 0 से 3 लाख रुपए | 0% |
| 3 लाख से 5 लाख | 5% |
| 5 लाख से 10 लाख | 20% |
| 10 लाख से ऊपर | 30% |

रेल बजट 2018

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने रेलवे को बेहतर बनाने के लिए एक रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित करने का ऐलान किया। यह विश्वविद्यालय गुजरात के शहर वडोदरा में स्थापित होगा। अरुण जेटली ने एक फरवरी को यूनियन बजट 2018 पेश करते हुए रेलवे के लिए 18 स्कूल भी खोलने का ऐलान किया। ये स्कूल देश के आईआईटी संस्थानों में खोले जाएंगे। इन स्कूलों में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग का काम होगा। वित्तमंत्री ने 600 रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इन स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए एक्स्क्लेटर (स्वचालित सीढ़ियां) लगाए जाएंगे। इसके साथ ही ट्रेनों में वाई फाई और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। अरुण जेटली अभी जी ने अपनी सरकार का चौथा बजट पेश किया। यूनियन बजट में मर्ज होने के बाद रेलवे का यह दूसरा बजट है। जेटली के पिटारे से रेलवे के लिए 1 लाख 48 हजार करोड़ रुपये निकले हैं। इस वर्ष का रेल बजट कुछ हद तक मुंबईवासियों की जरूरतों को पूरा करने वाला है। रेल बजट में मुंबई के लिए 90 किलोमीटर पटरी का विस्तार होगा। मुंबई में लोकल रेल का दायरा भी बढ़ाया जाएगा।

रेल बजट की मुख्य बातें

1. रेलवे स्टेशनों पर एक्स्क्लेटर, सीसीटीवी वाईफाई लगेंगे।
2. मुंबई लोकल का दायरा बढ़ाया जाएगा।
3. मुंबई में 90 किलोमीटर पटरी का विस्तार होगा।
4. 600 रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर जोर।
5. सुरक्षा बॉर्निंग सिस्टम पर जोर दिया जाएगा।
6. पूरा रेल नेटवर्क ब्रॉड गेज बनाया जाएगा।
7. पटरी, गेज बदलने जैसे काम पर खर्च किए जाएंगे पैसे।
8. 300 किलोमीटर रेल पटरियों का नवीनीकरण होगा।
9. 4000 से ज्यादा मानव क्रॉसिंग बंद किए जाएंगे।
10. माल ढुलाई के लिए 12 वैगन भी बनाए जाएंगे।
11. 3600 नई लाईनें बिछाई जाएंगी।
12. इस साल 700 नए रेल इंजन तैयार किए जाएंगे।
13. देश में अब सिर्फ बड़ी लाइनों पर रेल चलेगी।
14. 5160 नए कोच तैयार किए जाएंगे।
15. 40000 करोड़ रुपये एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे।

गरीब, किसान और गांवों के लिए बजट

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अगले आम चुनाव से पहले यह अंतिम पूर्ण बजट था। इस बजट में ध्यान गांव, ग्रामीण इलाकों, गरीबों और किसानों की ओर रहा। इस बार के बजट भाषण से सरकार की नीतियां दलित, पीड़ित, सोशित, वंचित और मजदूर वर्ग के लिए हैं

इस बार के बजट में किसानों के लिए क्या?

1. देश में कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिलाने के लिए सरकार काम कर रही है।
2. पशुओं के संवर्धन के लिए गोबरधन योजना चलाई जाएगी। पशु और मछली पालन के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का फंड वित्त मंत्री ने अलग से रखा है। उन्होंने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को एक बार फिर रेखांकित किया।
3. इसके अलावा नया ग्रामीण बाजार ई-नैम बनाने का ऐलान भी किया गया। जिला स्तर पर विशिष्ट कृषि उत्पादन का कलस्टर मॉडल विकसित किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने किसानों को क्रेडिट कार्ड देने की भी बात कही। खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1.5 गुना किया गया है।

कृषि से जुड़े बिजनेस को मिलेगा बढ़ावा

1. फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए 1400 करोड़ का प्रावधान किया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर देने की बात भी की। आलू और प्याज के उत्पादन के लिए ऑपरेशन ग्रीन लान्च करने के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है।
2. कृषि बाजार के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये की राशि का आवंटित की जाएगी। जिला स्तर पर विशिष्ट कृषि उत्पादन कलस्टर मॉडल विकसित करने की भी बात उन्होंने की।
3. इसके अलावा 42 मेगा फूड पार्क बनाने, बांस की पैदावार बढ़ाने के लिए 590 करोड़ रुपये देने की भी बात वित्त मंत्री ने की।
4. उन्होंने घोषणा की कि गांवों में 22 हजार हाटों को कृषि बाजार में तब्दील किया जाएगा। सोलर पावर को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कहा कि अतिरिक्त सौर ऊर्जा को सरकार खरीदेगी। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के लिए उन्होंने आवंटन राशि दोगुना करने की बात कही है।
5. कृषि उत्पादों के निर्यात को 100 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

गरीबों के लिए क्या निकला

1. वित्त मंत्री ने साल 2022 तक हर गरीब को घर देने के लक्ष्य को एक बार फिर दोहराया। शहरी क्षेत्रों में 37 लाख मकान बनाने की मंजूरी दी गई है।
2. स्वच्छता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए अरुण जेटली ने बताया कि 2018-19 में सरकार का लक्ष्य 2 करोड़ शौचालय बनाने का है। यही नहीं उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 6 करोड़ शौचालय बन चुके हैं।
3. 4 करोड़ परिवारों तक 16000 करोड़ रुपये की लागत से बिजली पहुंचाई जाएगी। उन्होंने अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए बताया कि 5 करोड़ गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य था, अब इस लक्ष्य को 8 करोड़ कर दिया गया है।
4. अनुसूचित जातियों के विकास के लिए 56619 करोड़ रुपये और जनजातियों के विकास के लिए 39135 करोड़ रुपये का आवंटन इस बजट में किया गया है। इसके अलावा जनजातियों के विकास के लिए 32000 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया जाएगा।

बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था

किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के लक्ष्य के मद्देनजर कम लागत में अधिक फसल उगाने पर जोर, किसानों को उनकी उपज का अधिक दाम दिलाने और उपज पर लागत से डेढ़ गुना अधिक दाम दिलाने का प्रस्ताव किया गया। दो हजार करोड़ रुपये की लागत से कृषि बाजार, कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए 1400 करोड़ रुपये और 500 करोड़ रुपये की लागत से ऑपरेशन ग्रीन चलाया जाएगा। इसके अलावा 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाने का ऐलान और गांवों में 22 हजार हाटों को कृषि बाजार में तब्दील किया जाएगा। साथ ही लघु और सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण कृषि बाजारों का विकास किया जाएगा।

क्या है

1. देश में कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है और साल 2022 तक किसानों की आय को दोगुना किया जायेगा। इसके लिए खरीफ की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1.5 गुना किया गया है।
2. जैविक खेती और महिला समूहों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही कृषि उत्पादों के निर्यात को 100 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा।
3. मछली पालन और पशुपालन व्यवसाय में 10000 करोड़ रुपये देकर ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की आय बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।
4. **सौभाग्य योजना के तहत** चार करोड़ गरीब घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी और गांवों में बुनियादी सुविधाएं को मजबूत करने के लिए 14.34 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत अब आठ करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाएगा।
5. नवोदय विद्यालय की तर्ज पर अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे। बीटेक विद्यार्थियों के लिए प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो योजना की भी घोषणा की गई है और 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज-अस्पताल खोलने की भी घोषणा की।
6. **पीएम जन-धन योजना** का भी विस्तार किया जाएगा। साथ ही पीएम दुर्घटना बीमा योजना के तहत 12 रुपये सालाना किश्त पर दो लाख रुपये के बीमा को 13.25 करोड़ लोगों ने अपनाया। जेटली ने कहा कि पीएम जीवन सुरक्षा बीमा योजना के तहत 330 रुपये सालाना प्रीमियम पर दो लाख रुपये बीमा योजना को 5.22 करोड़ लोगों ने अपनाया है।
7. **सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों के 80 हजार करोड़ की हिस्सेदारी बेच देगी।** वित्त मंत्री जेटली ने भाषण में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल का मानदेय बढ़ाते हुए सांसदों के वेतन को भी बढ़ाए जाने की बात कही। **राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपालों की परिलब्धियां बढ़ाकर क्रमशः पांच लाख, चार लाख और साढ़े तीन लाख रुपये प्रतिमाह की गईं।**
8. अगले वित्त वर्ष में दो करोड़ शौचालय बनाने के लक्ष्य का भी जिक्र किया। ग्रामीण क्षेत्रों में पांच लाख वाई फाई हाट स्पोर्ट और एक लाख ग्राम पंचायत हाईस्पीड ब्रॉडबैंड से जुड़ेंगी। इसके लिए 10 हजार करोड़ का आवंटन किया गया है। साथ ही उज्ज्वला योजना का लक्ष्य 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया।
9. सरकार ने **कामकाजी महिलाओं की जेब भरते हुए महिलाओं के ईपीएफ हिस्सेदारी को कम करके 8 फीसदी कर दिया है।** यानी जिन महिलाओं का वेतन कम है वह कम ईपीएफ कटवाकर ज्यादा पैसा खर्च के लिए रख सकती हैं। पहले यह करीब 9 फीसदी था। **सरकार ने इस साल नए कर्मचारियों के लिए यह बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया है।**

अहम घोषणाएं

1. सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 1.26 करोड़ खाते खुले, समावेशी समाज के सपने के लिए 115 जिले चिह्नित
2. अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए 39,135 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 56,619 करोड़ रुपये का प्रावधान
3. मुद्रा योजना के तहत तीन लाख करोड़ रुपये ऋण देने का लक्ष्य
4. नगर नियोजन एवं वास्तुशिल्प के दो नए विद्यालय खोले जाएंगे, 18 नए आईआईटी और एनआईआईटी भी बनेंगे।

5. 10 पर्यटन स्थलों को प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र बनाने की योजना
6. स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 99 शहरों का चुनाव कर लिया गया, जिसमें 2.04 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम होगा।
7. वित्त वर्ष 2018-19 में 9,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा
8. दस पर्यटन स्थलों को प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र बनाने की योजना
9. स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 99 शहरों का चुनाव कर लिया गया, जिसमें 2.04 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम होगा।
10. वित्त वर्ष 2018-19 में 9,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा
11. स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का बजट 2018-19 के लिए बढ़ाकर 1.38 करोड़ रुपये किया गया जो 2017-18 में 1.22 लाख करोड़ रुपये था।
12. विमानपत्तन प्राधिकरण के तहत वर्तमान में 124 हवाईअड्डे हैं। देश के हवाईअड्डों की यात्री वहन क्षमता को पांच गुना बढ़ाया जाएगा।
13. स्टाम्प ड्यूटी कानून में संशोधन पर विचार होगा
14. जिला अस्पतालों की सुविधाओं का उन्नयन करके 24 नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाए जाएंगे।
15. चारों सरकारी बीमा कंपनियां एक होंगी
16. सरकार 80000 करोड़ के शेयर बेचेगी
17. सरकार गोल्ड पॉलिसी बनाएगी
18. कंपनियों का भी आधार जैसा एक नंबर होगा
19. हर उद्योग के लिए अब अलग आईडी
20. बिटकवाइन जैसी करेंसी देश में नहीं चलेगी
21. वर्ष 2018-19 के लिए 80,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य; 2017-18 में विनिवेश से एक लाख करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान, जो तय लक्ष्य से अधिक है।
22. सांसदों के वेतन, भत्ते तय करने के नियमों में बदलाव होगा, मुद्रास्फीति से जुड़ेंगे, हर पांच साल में स्वतः संशोधन का नियम बनेगा।
23. बापू के 150वीं जयंती कार्यक्रमों के लिए 150 करोड़ रुपये।
24. वित्त वर्ष 2017-18 में राजकोषीय घाटा 3.2% से बढ़कर देश के सकल घरेलू उत्पाद का 3.5% हो गया। वित्त वर्ष 2018-19 में इसे 3.3% रखने का लक्ष्य।
25. इनकम टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं, छूट की सीमा पहले की तरह ढाई लाख रुपये
26. पंद्रह जनवरी, 2018 तक प्रत्यक्ष कर संग्रहण में 18.7 प्रतिशत की वृद्धि।
27. वित्तीय घाटा कम हुआ, इस साल 5.95 करोड़ रहा।
28. फुटवियर और चमड़ा उद्योग को नए रोजगार उपलब्ध कराने पर दी जाने वाली कर रियायत दी जाएगी।
29. वर्ष 2016-17 में वार्षिक 250 करोड़ रुपये का कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए कार्पोरेट कर घटाकर 25 प्रतिशत किया गया। कंपनियों के लिए कर दर कम करने से 2018-19 में 7,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान।
30. वेतनभोगी करदाता को 40,000 रुपये की मानक कटौती का लाभ दिया जायेगा; व्यक्तिगत आयकर दायरे में कोई बदलाव नहीं।
31. 2.50 करोड़ वेतनभोगी व पेंशनभोगियों को मानक कटौती का लाभ मिलेगा।
32. वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न जमाओं पर मिलने वाले 50,000 रुपये तक के ब्याज पर कर छूट मिलेगी, पहले यह सीमा 10,000 रुपये थी।
33. ट्रस्टों/संस्थानों द्वारा 10,000 रुपये से ज्यादा के नकद भुगतान पर रोक या कर देना होगा
34. स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर अब कुल मिलाकर 4% लगेगा
35. एक लाख रुपये से अधिक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 10 प्रतिशत कर

36. वर्ष 2018-19 के लिये रक्षा बजट बढ़ाकर 2.82 लाख करोड़ रुपये किया गया। चालू वित्त वर्ष में यह 2.67 लाख करोड़ रुपये था।

बजट में छोटी व मझोली कंपनियों को बड़ी सौगात

कारपोरेट टैक्स की दर में चरणबद्ध ढंग से कटौती की घोषणा पर अमल करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2018-19 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को बड़ी राहत दी है। जेटली ने सालाना 250 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए कारपोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का ऐलान किया। सरकार के इस कदम से देश की 7 लाख कंपनियों में से 99 प्रतिशत कंपनियों को राहत मिलेगी लेकिन खजाने पर इससे सात हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। सरकार ने हालांकि बड़ी कंपनियों को कारपोरेट टैक्स में कोई राहत नहीं दी है।

क्या है

1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को टैक्स में छूट मिलने से उनके पास निवेश के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध होगी जिससे अंततः रोजगार सृजन होगा। यह घोषणा ऐसे समय की है जब उद्योग जगत को मोदी सरकार के अंतिम पूर्ण बजट से कारपोरेट टैक्स की दर में कटौती के वादे को पूरा करने की उम्मीद थी।
2. कारपोरेट टैक्स में जो कटौती की है उसका लाभ उन्हीं कंपनियों को होगा जिनका टर्नओवर वित्त वर्ष 2016-17 में 250 करोड़ रुपये था।
3. देश में कुल सात ऐसी कंपनियां हैं जो हर साल आयकर रिटर्न दाखिल करती हैं। वित्त मंत्री का कहना है कि इनमें से 99 प्रतिशत कंपनियों को कारपोरेट टैक्स में कटौती का लाभ मिल जाएगा क्योंकि पिछले वित्त वर्ष में इनका टर्नओवर 250 करोड़ रुपये से कम था। हालांकि एक प्रतिशत कंपनियां ही ऐसी हैं जिनका सालाना टर्नओवर 250 करोड़ रुपये से अधिक है और उन्हें पूर्व की तरह 30 प्रतिशत की दर से कारपोरेट टैक्स देना होगा।
4. कारपोरेट टैक्स घटाने से 7000 करोड़ रुपये पड़ेगा खजाने पर बोझ।
5. आयकर दरों में कोई राहत नहीं, लेकिन सेस में 1 फीसदी की बढ़ोत्तरी।
6. सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार की कंपनियों को जो राहत दी है उससे वित्त वर्ष 2018-19 में खजाने पर भारी भरकम 7,000 करोड़ रुपये का बोझ भी पड़ेगा। अगर 250 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए भी कारपोरेट टैक्स की दर में कटौती की जाती तो इससे खजाने पर और अधिक बोझ पड़ता। राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने की चुनौती को ध्यान में रखते हुए ही वित्त मंत्री ने यह विकल्प चुना है।
7. पिछले बजट में वित्त मंत्री ने उन कंपनियों के लिए कारपोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का ऐलान किया था जिनका टर्नओवर वित्त वर्ष 2015-16 में 50 करोड़ रुपये तक था।
8. सरकार के इस कदम से आयकर रिटर्न दाखिल करने वाली 96 प्रतिशत कंपनियों को फायदा हुआ था। इसी से उत्साहित होकर उन्होंने सालाना 250 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए कारपोरेट टैक्स में कटौती की है।
9. एमएसएमई क्षेत्र को ऋण सहायता, पूंजी, ब्याज और इन्वोवेशन के लिए भारी भरकम 3794 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद मुहैया कराने की घोषणा भी की। साथ एमएसएमई क्षेत्र के फंसे कर्ज के संकट को दूर करने के लिए भी वित्त मंत्री ने उपाय करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश में एमएसएमई विकास और रोजगार के प्रमुख इंजन हैं।

भारी कर्ज के कारण रुका भारत की रेटिंग: फिच

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा कि सरकार पर कर्ज के भारी दबाव के कारण भारत की रेटिंग में सुधार रुक गया है। लगातार रेटिंग अपग्रेड करने के प्रयास में लगी सरकार के लिए यह किसी झटके से कम नहीं है। फिच का

बयान ऐसे समय में आया है, जब एक दिन पहले पेश बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी के 3.2 फीसद से बढ़ाकर 3.5 फीसद किया है।

क्या है

1. बजट में आर्थिक जरूरतों और सामाजिक बेहतरी के लिए कई नीतिगत कदमों की घोषणा की गई। इनमें कृषि से होने वाली आय में बढ़ोतरी और नए मेडिकल कॉलेज बनाने समेत महत्वाकांक्षी चिकित्सा बीमा योजना आदि शामिल हैं।
2. फिच रेटिंग (इंडिया) के डायरेक्टर एवं प्राइमरी सोवरेन एनालिस्ट थॉमस रूक्माकर ने कहा, 'यदि अच्छे से क्रियान्वयन हो, तो इन क्षेत्रों में किया गया खर्च मतदाताओं के एक बड़े वर्ग तक पहुंचेगा, जिसे आगामी चुनाव के लिहाज से महत्वहीन नहीं कहा जा सकता।' सरकार की कमजोर माली हालत ने भारत की सोवरेन रेटिंग के सुधार में रुकावट डाली है।
3. सरकार पर जीडीपी के करीब 68 फीसदी के बराबर कर्ज का बोझ है। यदि राज्यों को शामिल किया जाए तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.5 फीसद है। फिच ने पिछले साल मई में कमजोर वित्तीय स्थिति का हवाला देकर भारत की सोवरेन रेटिंग बीबीबी (माइनस) पर स्थिर रखी थी।
4. यह स्थिर परिदृश्य के साथ निवेश योग्य निम्नतम श्रेणी है। रूक्माकर ने कहा, 'सरकार ने राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3 फीसद तक सीमित रखने के लक्ष्य को 2020-21 तक के लिए टाल दिया है, जो मौजूदा सरकार के कार्यकाल से भी आगे है'।

भारतमाला के तहत अब तक 12 हजार हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत

'भारतमाला' परियोजना के तहत सरकार ने अब तक 12 हजार हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। करीब 8 हजार किलोमीटर सड़कों का डीपीआर भी तैयार हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार भारतमाला के पहले चरण के तहत कुल 24,800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाना है।

क्या है

1. इसमें से अब तक आठ हजार किलोमीटर सड़कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। भारतमाला के तहत बनने वाले प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 60 मीटर चौड़ाई की आवश्यकता को देखते हुए प्रति किलोमीटर 2 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता आंकी गई है।
2. इस हिसाब से 24 हजार किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 48 हजार हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता होगी। भारतमाला के तहत 800 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का निर्माण भी होगा। एक्सप्रेसवे के लिए 90 मीटर चौड़ाई की आवश्यकता के अनुसार 7200 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण और करना होगा।
3. भारतमाला के पहले चरण पर कुल 5.35 लाख करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

ग्रीन कार्ड के लिए EB-5 वीजा को तरजीह

अमेरिका में ग्रीन कार्ड पाने के लिए भारतीय ईबी-5 इन्वेस्टर वीजा को तवज्जो दे रहे हैं। इसके तहत अप्रवासियों को अमेरिका के किसी व्यापार में पूंजी लगानी होती है। इससे उनकी ग्रीन कार्ड पाने की योग्यता बढ़ जाती है और वह स्थायी रूप से अमेरिका में रह सकते हैं। पिछले चार साल में ईबी-5 वीजा के तहत आए आवेदनों की संख्या तीन गुना हो गई है। 2016 में करीब 350 आवेदन आए थे। 2017 के आंकड़े आने शेष हैं। सबसे ज्यादा व्यापारी और कॉरपोरेट क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारी ईबी-5 वीजा के लिए आवेदन देते हैं।

क्या है

1. यूएस फ्रीडम कैपिटल के मैनेजिंग निदेशक डेविड गंडर्सन ने कहा, 'अन्य वीजा के नियम कड़े होने से ईबी-5 की लोकप्रियता बढ़ी है'।

2. फिलहाल भारतीयों को इस वर्ग के तहत ग्रीन कार्ड पाने के लिए करीब 3.2 करोड़ रुपए अपनी पत्नी और अविवाहित बच्चों के नाम से निवेश करना होता है। इसके लिए किसी तरह की पढ़ाई या अन्य पैमाने की जरूरत नहीं होती है।
3. केवल निवेश की गई रकम वैध तरीके से कमाई गई हो तो ग्रीन कार्ड आसानी से मिल जाता है। ईबी-5 मिलने के बाद व्यक्ति पूरे अमेरिका में कहीं भी जाकर रह सकता है। हालांकि, ट्रंप सरकार इस राशि को बढ़ाकर प्रत्येक आवेदक के लिए लगभग 5.9 करोड़ रुपये करने पर विचार कर रही है।

अनक्लेमड फंड होगा सीनियर सिटीजन वेल्फेयर फंड में ट्रांसफर

बीमा नियामक इरडा ने सभी बीमाकर्ताओं को उन पॉलिसीहोल्डर्स के जमा को वेल्फेयर फंड में ट्रांसफर करने के लिए बोला है जो 10 वर्षों से बिना दावे के पड़ी हैं। नियामक ने यह ट्रांसफर एक मार्च तक करने के लिए बोला है। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने अपने सर्कुलर में कहा, “सभी बीमाकर्ता जिनके पास बिना दावे वाली राशि है जिसके 30 सितंबर, 2017 तक 10 वर्ष पूरे हो गये हैं तो उसे सीनियर सिटीजन वेल्फेयर फंड (एससडब्ल्यूएफ) में एक मार्च, 2018 तक या उससे पहले ट्रांसफर कर दें।” लाइफ, नॉन लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस सेवा प्रदाताओं को एससडब्ल्यूएफ नियमों, 2016 का अनुपालन करना होगा। इरडा ने कहा है कि यह ट्रांसफर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में एक मार्च, 2018 या उससे पहले हर साल ट्रांसफर कर दें।

क्या है

1. सीनियर सिटीजन वेल्फेयर फंड (एससडब्ल्यूएफ) को वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए ओल्ड एज पेंशन, लॉन्ग टर्म सेविंग्स इन्वेस्टमेंट, स्वास्थ्य और पोषण का प्रोत्साहन और किराया कीमत पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया है।
2. आम बजट में सरकार ने वित्तीय क्षेत्र में सुधार को लेकर बहुत लंबी चौड़ी घोषणाओं से परहेज किया है। हालांकि साधारण बीमा क्षेत्र में एक ऐसी घोषणा है, जो आने वाले दिनों में काफी असर डालेगी।
3. यह घोषणा है साधारण बीमा क्षेत्र की तीन सरकारी कंपनियों नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी और ओरियंटल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विलय की।
4. वर्ष 2000 में जब से बीमा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोला गया है, तब से इन सरकारी कंपनियों के सामने प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है।

विज्ञान एवं तकनीकी

विश्व कैंसर दिवस

नैनोमेडिसिन कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी तकनीक से भी ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। दिल्ली के दो वैज्ञानिकों ने हाल में कैंसर की सेल पर इस बारे में शोध किया है, जिसके बाद ये नतीजे सामने आये। इस शोध में सामने आया कि फाइकोसाइनिन ड्रग के अंदर एंटीकैंसर गुण विद्यमान हैं, जो कैंसर की सेल को खत्म कर सकते हैं। इससे दोबारा कैंसर होने की संभावना भी कम रहती है। भारत में पहली बार इस तरह का शोध हुआ है। यह शोध जर्नल ऑफ नैनो पार्टिकल रिसर्च में प्रकाशित हुआ है। अगर इसका उपयोग भारत में शुरू हुआ तो कैंसर के रोगियों को काफी फायदा होगा।

क्या है

1. शोध को दिल्ली के ही दो वैज्ञानिकों डॉ. सत्यम कुमार अग्रवाल और डॉ. मधुनिका अग्रवाल ने किया है। डॉ. सत्यम कुमार इस समय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में वैज्ञानिक हैं। उन्होंने बताया कि वैसे तो कैंसर के इलाज के लिए कई तकनीक हैं, उनके इस शोध करने का उद्देश्य यह था कि क्या यह ड्रग कैंसर को खत्म करने में ज्यादा कारगर है या नहीं।

2. उन्होंने बताया कि इस शोध में कैंसर के इलाज में कौन सा ड्रग ज्यादा ठीक है, इसे देखने के लिए उन्होंने फाइकोसाइनिन ड्रग के साथ पैक्लीटेक्सल नाम के एंटी कैंसर ड्रग से इसकी तुलना की है। ताकि यह सामने आ सके कि इनमें कौन ड्रग से कितना बेहतर है।
3. डॉ. अग्रवाल ने बताया कि स्पाइरुलिना नाम की एक एल्गी (समुद्र में पाई जाने वाली एक काई) होती है। इसके अंदर से ही फाइकोसाइनिन नाम का मॉल्युकूल (अणु) होता है। इसके सैंपल से ही उन्होंने शोध किया था।
4. जब इसको कैंसर के सेल पर टेस्ट किया गया तो पता चला कि इसमें एंटी कैंसर गुण मौजूद हैं। लेकिन यह सीधे तौर पर उतना मारक नहीं था। इसमें फाइकोसाइनिन का नेनोफॉर्म उस प्रभावित कैंसर सेल को ही खत्म कर रहा था। वहीं डॉ. सत्यम ने इसमें पैक्लीटेक्सल और फाइकोसाइनिन के नेनोफॉर्म के साथ भी इनका असर कैंसर सेल पर देखा। यह सबसे ज्यादा कैंसर सेल को खत्म कर रहा था।

इस तरह किया टेस्ट

1. बकौल डॉ. सत्यम, फाइकोसाइनिन के नेनोफॉर्म का उन्होंने स्वस्थ और कैंसर से प्रभावित दोनों ही सेल पर टेस्ट किया। इसका असर कैंसर से प्रभावित कोशिका पर ही हो रहा था। शोध में ब्रेन ट्यूमर की यू 87 एमजी कोशिका पर असर देखा गया था।
2. कीमोथरेपी में अमूमन में कई तरह के ड्रग मिलाकर मरीज को दिए जाते हैं। इसमें मरीज की स्वस्थ सेल पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है, यह कई बार कष्टदायी होता है। वहीं फाइकोसाइनिन ड्रग केवल कैंसर से प्रभावित सेल को ही खत्म कर रहा था। अमूमन धारणा है कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, इसमें फाइकोसाइनिन का उपयोग इसलिए किया ताकि लोगों को यह सस्ते में मिल सके।
3. यह सभी तरह के कैंसर के लिए फायदेमंद है। यह शोध ब्रेन ट्यूमर के लिए हुआ था, लेकिन माना गया है कि यह कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी कारगर है।

क्या हैं नैनोफॉर्म मेडिसन

1. नैनोमेडिसन मूलतः उसी जगह पर असर करती है, जहां इसका असर दिखाना पड़ता है। माने दिमाग में यदि कोई सेल कैंसर से प्रभावित है तो यह उसी जगह जाकर असर दिखाएगा।
2. फिलहाल फाइकोसाइनिन का उपयोग भारत में नहीं हो रहा है। बाजार में यह सप्लीमेंट के तौर पर उपयोग होता है। कई बार कैंसर के इलाज में लोगों को सर्जरी के बाद आराम दिलाने के लिए फाइकोसाइनिन का प्रयोग किया जा सकता है।
3. 2500 लोग हर साल तंबाकू की वजह से भारत में मर जाते हैं
4. 1 महिला हर आठ मिनट में कैंसर के कारण मरती है।
5. 14.5 लाख कैंसर के मामले 2016 में सामने आये थे, यह बढ़कर 2020 तक 17.3 लाख हो जाएंगे।

स्पेस की सैर कराने के ऑफर शुरू करेगा रूस

रूस अब पर्यटकों को स्पेस की सैर कराने की योजना बना रहा है। अपने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के जरिए के पैसे देकर स्पेस की सैर करने की इच्छा रखने वाले यात्रियों को ऑफर शुरू किए जाएंगे। स्पेस की सैर के लिए अपना नाम पहले देने वाले शख्स को भारी छूट दी जाएगी। रूस की स्पेस कंपनी इनर्जिया के प्रमुख ने मीडिया को बताया कि वे इस योजना की संभावनाओं के बारे में बातचीत कर रहे हैं। एक यात्री की स्पेस ट्रिप में करीब 100 मिलियन डॉलर से कम का खर्च आएगा। उन्होंने बताया कि यात्रियों को एक ऐसे यान से भेजे जाने की योजना है जिसमें से वह स्पेस में ही बाहर निकल सकें और वहां घूम-घूम कर वीडियो शूट कर सकें और फोटोग्राफी कर सकें।

क्या है

1. एनर्जिया वही कंपनी है जिसने 1961 में यूरी गागरिन नाम वैज्ञानिक को अंतरिक्ष में भेजा था। गागरिन ही अंतरिक्ष में कदम रखने वाले पहले यात्री थे। यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर कराने के लिए अभी विशेष प्रकार के अंतरिक्ष यान को तैयार किया जा रहा है।

2. कंपनी ने बताया कि तैयार किए जा रहे यान में 4 से 6 लोग आराम से बैठ सकेंगे। इस यान में दो शौचालय और इंटरनेट एक्सेस की सुविधा होगी। इस यान को 2019 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।
3. अमेरिकी विमानन कंपनी बोइंग भी इस यान का हिस्सा बनने के लिए रुचि दिखा रही है। उन्होंने बताया कि इस स्पेस शटल को साल में एक बार 10 दिन की सैर के लिए यात्रियों को भेजा जाएगा। यानी एक साल में 4 से 6 यात्री ही स्पेस की सैर कर पाएंगे।
4. इरानी मूल का अमेरिकी नागरिक अनौशेह अंसारी इससे पहले 2006 में पहला अंतरिक्ष टूरिस्ट बन चुका है।

क्या पृथ्वी से खत्म हो जाएगा जीवन

करोड़ों वर्ष पहले मंगल पर वायुमंडल था, लेकिन वहां के चुंबकीय क्षेत्र के धीरे-धीरे खत्म होने से सौर तूफानों ने उसे तबाह कर दिया। अब ऐसा ही संकट पृथ्वी पर आने वाला है। इसके चुंबकीय क्षेत्र पर भी खतरा मंडरा रहा है। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पलट सकते हैं। इससे इसका चुंबकीय कवच कमजोर पड़ जाएगा। सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी के वायुमंडल को चीरती हुई सतह तक आ जाएंगी। और मंगल की ही तरह पृथ्वी के वायुमंडल का खात्मा यहां के जीवन के अंत की वजह बन सकता है।

क्या है

1. वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी के कोर में मौजूद तरल लोहा विशालकाय इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बर्ताव करता है, जिसके दो चुंबकीय ध्रुव हैं। इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट पैदा होता है, जो पृथ्वी के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटोस्फेयर तैयार करता है।
2. अंतरिक्ष में हजारों मील तक फैला हुआ यह चुंबकीय क्षेत्र सूर्य की घातक किरणों से पृथ्वी को बचाता है। धरती पर मौजूद जीवन इसी कवच पर निर्भर करता है। इसके खत्म हो जाने के बाद जीवन खत्म होने में समय नहीं लगेगा।
3. पुराने अध्ययनों के मुताबिक पृथ्वी के इतिहास में हजारों बार चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव आया है।
4. धरती के कोर में मौजूद तरल लोहा स्थिर नहीं है। इसके कारण पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव हर दो या तीन लाख वर्ष में आपस में जगह बदल लेते हैं।
5. यूरोपीय स्पेस एजेंसी के उपग्रहों द्वारा एकत्र किए डाटा के मुताबिक हर दशक में पृथ्वी का चुंबकीय कवच पांच फीसद की दर से कमजोर पड़ रहा है। यह दर पूर्व अनुमान से दस गुना अधिक है।
6. कुछ अध्ययनों के मुताबिक पिछली बार यह बदलाव 7. 80 लाख वर्ष पहले हुआ था।
7. इस प्रक्रिया में चुंबकीय क्षेत्र धीरे-धीरे कमजोर पड़ता जाता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि अगला बदलाव शुरू हो चुका है।
8. दक्षिणी अमेरिका के ऊपर मौजूद चुंबकीय क्षेत्र सबसे तेजी से कमजोर पड़ रहा है। इस क्षेत्र को वैज्ञानिकों ने दक्षिण अटलांटिक असंगति नाम दिया है। इस क्षेत्र के ऊपर से गुजरने वाले उपग्रहों के सर्किट रेडिएशन बढ़ जाने के कारण खराब हो गए।
9. अमेरिका के कोलाराडो स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कोलाराडो

तीन साल पहले मिला संकेत

1. 2015 में सूर्य से निकालने वाली तीव्र किरणों ने सुपरस्टॉर्म की स्थिति खड़ी कर दी। लगातार दो घंटों तक घातक किरणों के बरसने से पृथ्वी के मैग्नेटोस्फेयर में अस्थायी दरारें पड़ गईं।
2. प्रकाश की गति से अत्यधिक तेज रेडिएशन पृथ्वी पर हुआ, उनसे वातावरण में जियोमैग्नेटिक तूफान उठा। ध्रुवों के करीब क्षेत्रों में रेडियो सिग्नल ठप्प पड़ गए।
3. वैज्ञानिकों के एक समूह के मुताबिक ध्रुव पलटने से सौर विकिरण दोगुना हो जाएगा। इससे हर साल कैंसर जैसी बीमारियों से एक लाख लोगों की जान जा सकती है।
4. दूसरे समूह का कहना है कि चुंबकीय परत भले ही कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन सौर विकिरण में मामूली इजाफा होगा। कमजोर कवच के बाद भी पृथ्वी का घना वातावरण सूर्य की घातक किरणों को रोक लेगा।

के अंतरिक्ष विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर यह सारे संकेत सही हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र के पलटने के बाद पृथ्वी के कुछ क्षेत्र रहने लायक नहीं बचेंगे।

10. भारत के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने एक वर्ष बाद दावा किया कि घातक किरणों ने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को पीछे धकेल दिया है। यह क्षेत्र जो पृथ्वी के अर्द्धव्यास का 11 गुना अधिक था, वह अब सिर्फ चार गुना रह गया है।

HIV के किफायती जांच में सफलता

वैज्ञानिकों को एचआइवी जांच की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने पेपर आधारित ऐसी नई जांच विकसित की है जिससे इस रोग का शुरुआती अवस्था में ही पता लगाना संभव हो सकेगा। यह जांच किफायती और बेहद संवेदनशील है। ब्रिटेन के इंपीरियल कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने यह नई जांच ईजाद की है। इसका उपयोग इबोला और जीका जैसे संक्रमणों की पहचान करने में भी हो सकता है।

क्या है

1. हाल के वर्षों में इबोला और जीका जैसे रोगों के चलते बहुत लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं, जबकि एचआइवी अब भी कई लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बना हुआ है।
2. इसमें सबसे बड़ी समस्या खासतौर पर विकासशील देशों में है जहां संक्रामक रोगों का आमतौर पर लंबे समय तक पता ही नहीं चल पाता। नतीजतन ये महामारी का रूप ले लेते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ताओं ने एचआइवी के लिए किफायती जांच विकसित की है।
3. वैज्ञानिकों ने शरीर में एचआइवी संक्रमण होने की पूरी प्रक्रिया का पता लगा लिया है। इस खोज से एचआइवी का इलाज ढूंढने में सहायता मिल सकती है। एचआइवी पहले एक कोशिका को संक्रमित करता है, फिर संक्रमित कोशिका की झिल्ली विघाणुओं से भरे कैप्सूल का निर्माण कर लेती है। ये कैप्सूल जनक कोशिका से निकलकर शरीर की अन्य कोशिकाओं को संक्रमित करता है।
4. इस प्रक्रिया को बडिंग कहा जाता है। शिकागो विवि के ग्रेगरी वोथ ने कहा, बडिंग के बाद शरीर में जो संरचना बनती है उसकी जानकारी थी लेकिन प्रक्रिया का अनुमान नहीं था।
5. इस प्रक्रिया में गैग प्रोटीन नामक एचआइवी प्रोटीन की जटिल संरचना सम्मिलित होती है। हमारी टीम ने एक कंप्यूटर मॉडल बनाकर गैग की प्रक्रिया का पता लगाया। अब एचआइवी के इलाज के लिए उपचार ढूंढना आसान होगा।

विविध

नयी रोस्टर प्रणाली लागू

सुप्रीम कोर्ट ने जजों के बीच काम के बंटवारे का नया रोस्टर सिस्टम तय कर दिया है। नयी व्यवस्था पांच फरवरी से लागू होगी। इसमें पीठों के हिसाब से केसों की सुनवाई की श्रेणी तय की गई है। इसके मुताबिक जनहित याचिकाएं मुख्य न्यायाधीश ही सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजों के बीच काम के बंटवारे का रोस्टर पहली बार सार्वजनिक किया गया है। ये रोस्टर सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर 1 फरवरी 2018 को डाल दिया गया है। चार वरिष्ठ जजों का प्रेस कान्फ्रेंस कर जजों को कार्य आवंटन पर सवाल उठाए जाने और मुख्य न्यायाधीश पर महत्वपूर्ण मामले पसंदीदा पीठ को दिये जाने के आरोपों के बीच मुख्य न्यायाधीश द्वारा नया रोस्टर जारी करना और उसे सार्वजनिक करने को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उम्मीद की जाती है कि इससे जजों के प्रेस कान्फ्रेंस के बाद उठा विवाद निपट जाएगा।

क्या है

1. नये रोस्टर के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर नये केसों की सुनवाई के लिए जजों के बीच कार्य बंटवारे का रोस्टर जारी किया गया है।
2. मुख्य न्यायाधीश की पीठ सहित कुल 12 कोर्टों में पीठ की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीशों के नाम से कार्य का श्रेणीवार बंटवारा किया गया है।

3. कोर्टों का क्रम न्यायाधीशों की वरिष्ठता के हिसाब से तय होता है। कोर्ट नंबर एक यानी मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष सर्विस मैटर, जनहित याचिकाएं, सामाजिक न्याय, चुनाव संबंधी, मध्यस्थता मामले, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं, क्रिमिनल मैटर, न्यायालय की अवमानना, दीवानी मामले, संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, विधायी नियुक्तियां और जांच आयोग के मामले सुने जाएंगे।
4. कोर्ट दो जस्टिस चेलमेश्वर की पीठ लेबर ला, अप्रत्यक्ष कर, भूमि अधिग्रहण आदि मामले सुनेगी। कई श्रेणियों का आवंटन एक से ज्यादा पीठों के पास रखा गया है। शायद ऐसा काम की अधिकता और केस के निपटारे की सुगमता को देखते हुए किया गया होगा।
5. जस्टिस लोकर की पीठ अन्य मामलों के अलावा पर्यावरण और सामाजिक न्याय से जुड़े मामले भी सुनेगी। हालांकि जनहित याचिकाएं सिर्फ मुख्य न्यायाधीश की पीठ ही सुनेगी।
6. वैसे चीफ जस्टिस मास्टर आफ रोस्टर होता है और वही तय करता है कि कौन सा केस किस पीठ के पास सुनवाई के लिए जाएगा। अभी हाल ही में चीफ जस्टिस के इस अधिकार पर पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मुहर लगाई थी। लेकिन विवाद उठने के बाद लगातार रोस्टर व्यवस्था पारदर्शी बनाने की मांग हो रही थी।

भारत चौथी बार बना वर्ल्ड चैंपियन

भारत ने ऑस्ट्रेलिया को आठ विकेट से हराकर रिकार्ड चौथी बार अंडर 19 विश्व कप जीत कर इतिहास रच दिया। अंडर 19 क्रिकेट टीम ने 'गुरू' राहुल द्रविड़ को उनके कोचिंग कैरियर की सबसे बड़ी कामयाबी से नवाजा। भारतीय गेंदबाजों ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए आस्ट्रेलिया को 216 रन पर आउट कर दिया। जवाब में भारत ने सिर्फ दो विकेट खोकर 38.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया।

क्या है

1. दिल्ली के मनजोत कालरा ने 102 गेंद में नाबाद 101 रन बनाये जबकि कप्तान पृथ्वी शां और टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले शुभमान गिल आज जल्दी आउट हो गए थे। भारत ने चौथा खिताब जीतकर आस्ट्रेलिया को पछाड़ा जिसके नाम तीन खिताब हैं।
2. यह प्रदर्शन कोच द्रविड़ को भी शानदार तोहफा रहा जिन्हें आखिरकार विश्व कप ट्राफी अपने नाम करने का मौका मिला। दो साल पहले बांग्लादेश में टीम उपविजेता रही थी। भारत ने छह साल पहले उन्मुक्त चंद की अगुवाई में यह खिताब जीता था। विराट कोहली ने 2008 और मोहम्मद कैफ ने 2000 में खिताबी जीत दिलाई थी।
3. इस बार भारत शुरू ही से प्रबल दावेदार माना जा रहा था और प्रदर्शन भी उसी तरह का रहा। दूसरी टीमों और भारत के प्रदर्शन में जमीन आसमान का अंतर था।

बेटी को भी जन्म से ही है पैतृक संपत्ति में हक

सुप्रीम कोर्ट ने पिता की पैतृक संपत्ति में हिन्दू लड़की के हक पर अहम व्यवस्था दी है। कोर्ट ने कहा है कि हिन्दू उत्तराधिकार कानून 1956 के बनने से पहले पैदा हुई लड़की को भी पिता की संपत्ति में पुत्रों के बराबर हक है। कानून की व्याख्या करते हुए कोर्ट ने कहा है कि 2005 में हिन्दू उत्तराधिकार कानून में किये गए संशोधन में बेटी को पिता की संपत्ति में जन्म से अधिकार दिया गया है जैसा कि पुराने कानून में बेटे को मिला है। ऐसे में बेटी को भी बेटे की तरह संपत्ति में जन्म से अधिकार मिलेगा। दोनों पैतृक संपत्ति में जन्म से सहभागी माने जाएंगे।

क्या है

1. यह अहम व्यवस्था न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी व न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने गत 1 फरवरी को कर्नाटक की दो बहनों के पिता की संपत्ति में हक पर मुहर लगाते हुए दी।
2. निचली अदालत और कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह कहते हुए बेटियों की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग खारिज कर दी थी कि उनका जन्म हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के बनने से पहले हुआ था।

3. इतना ही नहीं बेटियों की ये दलील भी खारिज कर दी थी कि 2005 में हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम में हुए संशोधन के बाद उन्हें पिता की संपत्ति में कानूनन हक मिला है।
4. सुप्रीम कोर्ट ने पिता की संपत्ति में दोनों बहनों को हिस्सेदारी देते हुए अपने फैसले में कहा कि मिताक्षरा से संचालित होने वाले हिन्दू अविभाजित परिवार के कानून में अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। ये बदलाव संपत्ति में हक रखने वाले सहभागी के नजदीकी महिला रिश्तेदार जैसे बेटे को बराबरी का हक देने के लिए किया गया। कानून में कहा गया है कि बेटे संपत्ति में जन्म से साझी हिस्सेदार होगी और उसके भी वही अधिकार और जिम्मेदारियां होंगी जो बेटे की होती हैं। बेटे साझी हिस्सेदार होगी और उसे वह संपत्ति वसीयत या किसी और तरीके से निस्तारित करने का भी हक होगा।
5. कोर्ट ने कहा कि बेटे के साथ भेदभाव खत्म करने और उसे बराबरी का हक देने के लिए ये बदलाव किये गये। **हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में ये मूलभूत बदलाव 2005 के संशोधन के जरिये किये गए। 2005 के संशोधित कानून की धारा 6 कहती है कि बेटे जन्म से ही संपत्ति पर उसी तरह साझी हिस्सेदारी की अधिकारी होगी जैसे कि बेटा होता है।** कोर्ट ने कहा कि पुराना हिन्दू कानून बेटे को जन्म से संपत्ति का साझा हिस्सेदार मानता है ऐसे ही संशोधित कानून में बेटे को जन्म से साझा हिस्सेदार माना गया है। कानून में ठीक वैसे ही शब्द प्रयोग किये गये हैं जैसे बेटे के लिए किये गये हैं। इसलिए बेटे और बेटे दोनों का संपत्ति पर जन्म से साझा हक होगा।

क्या है मामला

1. कर्नाटक के गुरुलिंगप्पा सावादी अविभाजित हिन्दू परिवार के थे। उनकी 2001 में मृत्यु हो गई। उनके दो बेटे, दो बेटियां व पत्नी थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके पोते ने संपत्ति में बटवारे का मुकदमा किया।
2. मुकदमें में गुरुलिंगप्पा की दोनों बेटियों को संपत्ति का साझा हिस्सेदार नहीं बनाया गया। दलील थी कि इन बेटियों का जन्म हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के आने से पहले हुआ था।
3. ये भी कहा कि इनकी शादी हो चुकी है और उसमें इन्हें सोना और पैसा मिला था इसलिए इन्होंने अपना हिस्सा छोड़ दिया है। दोनों लड़कियों ने पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी मांगी थी। निचली अदालत और हाईकोर्ट से निराश होने के बाद दोनों बहनें सुप्रीम कोर्ट आयीं थीं।

फोर्ब्स इंडिया: 30 से कम उम्र के हस्तियों का नाम शामिल

फोर्ब्स इंडिया ने 30 से कम उम्र के 30 अमीर भारतीयों की लिस्ट जारी कर दी है। फोर्ब्स की इस लिस्ट में मूर्तिकार साहिल नायक, क्षितिज मारवा, रंजन बोरडोली, गौरव मुंजाल, रोमन सैनी, हिमेश सिंह और रोहित रामसुब्रमण्यन, जसप्रीत बुमराह, भूमि पेडनेकर समेत 30 जानीमानी हस्तियों का नाम शामिल किया गया है। फोर्ब्स ने 15 कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए ये लिस्ट बनाई है। **आर्ट एंड कल्चर, डिजाईन, इ-कॉमर्स, एंटरटेनमेंट, फैशनम म्यूजिक, मनोरंजन, कला, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, मेडिकल** इस लिस्ट की प्रमुख कैटेगरी हैं। तीन स्टेज के रिसर्च प्रॉसेस के बाद फोर्ब्स इंडिया ने 30 से कम उम्र वाले इन भारतीय अमीरों के नाम का चुनाव किया है। पहले चरण में फोर्ब्स इंडिया टीम ने सभी कैटेगरीज से जुड़े लोगों का साक्षात्कार किया। साथ ही साथ इन लोगों के डेटाबेस और इनसे जुड़ी मीडिया कवरेज की पूरी स्टडी की। दूसरे चरण में फोर्ब्स इंडिया डॉटकॉम पर उद्यमियों और प्रोफेशनल्स के नामांकन के लिए आवेदन किया। फिर सोशल मीडिया पर सूचना प्रसारित की गई। इस पूरी प्रक्रिया के बाद **फोर्ब्स इंडिया के पास 15 कैटेगरीज में 300 नामों की लिस्ट तैयार हुई।** अंतिम चरण में इन 300 नामों में से 30 नामों का चुनाव हुआ। **इस लिस्ट में शामिल सभी हस्तियां 31 दिसंबर 2017 तक 30 साल से कम उम्र की हैं।**

प्रमुख हस्तियां

1. **साहिल नाइक (आर्ट कैटेगरी)** - गोवा के पोंडा में पले बड़े 26 वर्षीय साहिल नाइक मशहूर मूर्तिकार हैं।

2. **क्षितिज मारवा (डिजाइन कैटेगरी)** - 29 वर्षीय डिजाइन इनोवेटर क्षितिज ने दुनिया का पहला होलोग्राफिक एआर हेडसेट विकसित किया है जो स्मार्टफोन के साथ काम करता है।
3. **रंजन बोरडोली (डिजाइन कैटेगरी)** - गुवाहाटी से ताल्लुक रखने वाले 27 वर्षीय रंजन बोरडोली स्टूडियो बोरडोली के संस्थापक और क्रिएटिव डायरेक्टर हैं।
4. **गौरव मुंजाल, रोमान सैनी, हिमेश सिंह (इकॉमर्स कैटेगरी)** - गौरव मुंजाल (27 वर्ष), रोमान सैनी (26 वर्ष), हिमेश सिंह (25 वर्ष) अनएकेडमी के को-फाउंडर हैं। वर्ष 2010 में मुंबई में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही गौरव मुंजाल ने कंप्यूटर ग्राफिक्स पर शॉर्ट वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड करना शुरू किया।
5. **रोहित रामासुब्रमनियन, करन गुप्ता, हिमेश जोशी, अर्जित गुप्ता (इकॉमर्स कैटेगरी)** - रोहित रामासुब्रमनियन (27 वर्ष), करन गुप्ता (28 वर्ष), हिमेश जोशी (29 वर्ष), अर्जित गुप्ता (29 वर्ष) के इकॉमर्स कैटेगरी में इस लिस्ट में शामिल किया गया है।
6. **भूमि पेडनेकर (एंटरटेनमेंट)** - बॉलिवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने अपने दमदार अभिनय से बहुत कम समय में माया नगरी में अपनी पहचान बना ली।
7. **विक्की कौशल (एंटरटेनमेंट)** - फिल्म मसान से मशहूर अभिनेता विक्की कौशल को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है।
8. **मिथिला पालकर** - 24 साल की मिथिला पालकर यूट्यूब की दुनिया में जाना-माना चेहरा है। एक छोटे से रोल में वो इमरान खान और कंगना रनौत की फिल्म 'कट्टी बट्टी' में नजर आई थीं।
9. **एलेन अलेक्सेंडर कलीकल (फैशन)** - 29 साल के एलेन कलीकल के फाउंडर और क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। एलेन ने एप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रुमेंटेशन की पढ़ाई की, उनका रुझान इस इंजीनियरिंग की दुनिया में नहीं था।
10. **सुहानी पारेख (फैशन)** - 26 साल की सुहानी मिशो कंपनी की संस्थापक और क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। हालांकि सुहानी ने लंदन यूनिवर्सिटी में मूर्तिकार की ट्रेनिंग ली लेकिन उनका मन यहां नहीं रमा।

सर्विस सेक्टर को मिली रफ्तार

जनवरी 2018 के दौरान सर्विस पीएमआई में बढ़त दर्ज की गई है। सर्विस पर्चेजिंग मैनेजर इंडेक्स (पीएमआई) जनवरी महीने में 51.7 पर रहा है। यह निक्केई की ओर से जारी की गई जानकारी में यह बात सामने आई है। दिसंबर महीने के दौरान सर्विस पीएमआई में मामूली बढ़त दर्ज की गई थी। दिसंबर 2017 में यह 50.9 के स्तर पर था। वहीं, नवंबर महीने में सर्विस पीएमआई 48.5 के स्तर पर रहा था। आपको बता दें कि पीएमआई में 50 से ऊपर का स्तर अर्थव्यवस्था में विस्तार और 50 से नीचे का स्तर अर्थव्यवस्था में संकुचन की स्थिति को दर्शाता है।

क्या है

1. आईएचएल मार्किट की अर्थशास्त्री आशना डोडिया ने बताया, “जनवरी में भारत के सेवा अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिला है”। यह स्तर जून 2017 के बाद से सबसे मजबूत है। साथ ही इसके मांग में सुधार देखने को मिला है।
2. भारतीय सेवा प्रदाताओं ने जनवरी महीने में लगातार पांचवें महीने पिछले लंबित कार्यों और नये कारोबारी ऑर्डर्स के मद्देनजर कार्यबल में विस्तार किया है। इसके अलावा सितंबर महीने से रोजगार सृजन की दर सबसे ज्यादा रही है।
3. **विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर जनवरी में तीन महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है।** इसके मुख्य कारण कारखानों का उत्पादन, नये ऑर्डर और रोजगार वृद्धि का धीमा रहना रहा है।
4. निक्केई इंडिया का विनिर्माण पीएमआई जनवरी में कमजोर होकर 52.4 पर पहुंच गया जबकि दिसंबर महीने में यह 60 महीने (पांच वर्ष) के उच्च स्तर यानी 54.7 पर रहा था।
5. यह लगातार छठा महीना है जब विनिर्माण पीएमआई 50 से ऊपर रहा है।

गोवा में 88 खदानों के लाइसेंस रद्द

गोवा में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन मामले में 7 फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने 80 से अधिक खदानों के लाइसेंस रद्द कर दिए। जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आदेश दिया कि अब नई नीति के तहत खदानों का आवंटन होगा। इसके लिए नई खदानों को फिर से पर्यावरणीय मंजूरी लेनी होगी। गोवा सरकार ने 2015 में कंपनियों को 20 साल के लिए खदान के लाइसेंस दिए थे ये लाइसेंस पिछली तिथि से प्रभावी थे।

क्या है

1. कोर्ट ने नियमों का उल्लंघन कर की गई माइनिंग की एसआईटी जांच में तेजी लाने और रिकवरी किए जाने के भी आदेश दिए हैं।
2. कोर्ट के आदेशानुसार कंपनियों को 16 मार्च तक कामकाज समेटना होगा। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को नीलामी के जरिए नये सिरे से खदान लाइसेंस देने को कहा है।
3. राज्य की सभी 88 माइनिंग लीज को रद्द कर दिया है। 2007 से 20 साल के लिए रिन्यू किए गए लीज को रद्द करते हुए जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता वाली बेंच ने कहा कि गोवा सरकार कानून के तहत माइनिंग लीज के लिए आवेदनों की जांच करेगी। लौह व मैंगनीज अयस्क समेत तमाम खदानों में 15 मार्च के बाद काम को रोक दिया जाएगा।
4. इस मामले में एनजीओ गोवा फाउंडेशन ने याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन खनन कंपनियों पर रोक लगाते हुए आदेश दिया कि सरकार की तरफ से लीज 16 मार्च तक के लिए आवंटित की गई थी।
5. कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि गोवा में माइनिंग लीज के लिए सरकार नए सिरे से नीलामी करवाए। आरोप है कि गोवा की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 88 खदानों के लीज गलत तरीके से कुछ लोगों के लाभ के लिए आवंटित किया था। इस मामले में गोवा सरकार का कहना है कि सभी निश्चित प्रक्रियाओं का लीज आवंटन में पालन किया गया है।
6. गोवा में खनन घोटाला एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है और इसमें कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिगम्बर कामत से भी एसआईटी पूछताछ हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय खनन मंत्रालय द्वारा राज्य के बड़े अवैध घोटाले के मामले में आरोपी गोवा की लगभग सभी खनन कंपनियों और साथ ही कई शीर्ष नौकरशाहों और नेताओं की जांच के लिए न्यायमूर्ति एम.बी. शाह की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी।
7. गोवा की अर्थव्यवस्था में लौह अयस्क का खनन गोवा की अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है। हालांकि राज्य में 35,000 करोड़ रुपये के अवैध खनन घोटाले के बाद 2012-2014 तक दो सालों के लिए कई अरब रुपयों के इस उद्योग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
8. गोवा ने करीब 5.5 करोड़ टन लौह अयस्क का निर्यात किया था। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने, जो अवैध खनन के इस मामले की सुनवाई कर रहा है, प्रतिबंध के बाद लौह अयस्क के खनन पर प्रति वर्ष 20 टन की सीमा तय कर दी है।

सबसे बड़े वाइल्डलाइफ सर्वे से होगी बाघों की गिनती

देश में बाघों की संख्या का अनुमान लगाने की चौथी कोशिश शुरू हो गई है। इसे ज्यादा सटीक बनाने के लिए प्रक्रिया का पूरी तरह डिजिटाइजेशन किया गया है। आकलन एक एंड्रॉयड फोन बेस्ड एप्लिकेशन और डेटा को एकत्र, जमा और विश्लेषण करने के लिए M-STRIPES के डेस्कटॉप वर्जन पर आधारित होगा। M-STRIPES बाघों के संरक्षण और पर्यावरणीय स्थिति की निगरानी का सिस्टम है। देश में बाघों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए प्रत्येक चार वर्षों में उनकी गिनती की जाती है। यह दो चरणों में होती है।

क्या है

1. पहले चरण में बाघ के पंजों के निशान के आधार पर डेटा एकत्र करने के लिए 18 राज्यों में फॉरेस्ट गार्ड और अधिकारियों को भेजा जाता है। इस डेटा को पहला सैंपल माना जाता है।

2. दूसरे चरण में बायोलॉजिस्ट कैमरा ट्रैप इंस्टॉल कर डेटा हासिल करते हैं। इसके बाद दोनों सैंपल का एक कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से मिलान किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर बाघों की व्यक्तिगत पहचान उनके शरीर पर बनी धारियों के आधार पर करता है।
3. नए सिस्टम के तहत, सैंपल लेने की दोहरी तकनीक समान है, लेकिन इसके साथ एक फोन बेस्ड एप्लिकेशन जोड़ी गई है। यह ऐप पहले सैंपल को एकत्र करने के लिए सर्वे के ट्रैक लॉग और वन अधिकारियों की ओर से लिए गए रास्तों और दूसरे सैंपल में बायोलॉजिस्ट के आंकड़ों का रिकॉर्ड ऑटोमैटिक तरीके से दर्ज करती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा वाइल्डलाइफ सर्वे होने की उम्मीद है।
4. वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट वाई वी झाला ने कहा, 'हम डिजिटाइजेशन के साथ बाघों की गिनती की सटीकता को सुधारने में सक्षम होंगे।' इसमें पूर्वोत्तर का एक नया क्षेत्र भी कवर किया जाएगा। पिछले तीन सर्वेक्षण में सैंपल को ठीक तरीके से एकत्र नहीं किया गया था।
5. इसबार कैमरा लोकेशंस को भी बढ़ाया गया है। 2014 के सर्वे में 9,000 कैमरा लोकेशंस का इस्तेमाल किया गया था, जो इस बार बढ़ाकर 14,000 की गई हैं।
6. बाघों की संख्या के साथ ही बायोलॉजिस्ट्स को तेंदुओं की संख्या का अभी अनुमान मिलेगा। झाला ने बताया, 'हम पहले यह देख चुके हैं कि केवल पंजों के निशान बाघों की संख्या से जुड़ा डेटा एकत्र करने का सटीक तरीका नहीं है।'

'मंकी फीवर' ने भारत में ले ली कई जान

भारत के कुछ हिस्सों में जबरदस्त मंकी फीवर का खौफ है। इसने अब तक 19 लोगों को बेमौत काल के गाल में पहुंचा दिया है। मंकी फीवर को क्यासनुर फॉरेस्ट डिजिज (केएफडी) भी कहा जाता है जो धीरे-धीरे फैलता है। 2016 में पहली बार पुष्टि के बाद से भारत में अब तक 322 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 19 लोगों की मौत हो चुकी है। इसे क्यासनुर फॉरेस्ट डिजिज (केएफडी) भी कहा जाता है जो धीरे-धीरे फैलता है।

मंकी फीवर के लक्षण

1. मंकी फीवर के पीड़ित अक्सर तेज बुखार या फिर ब्लीडिंग होने की शिकायत करते हैं।
2. इसके चलते शरीर में कंपकंपी, मानसिक अशांति का अहसास होता है। यही नहीं अनदेखी पर मौत भी हो सकती है।
3. बीमारी घातक रूप पांचवें दिन के बाद लेना शुरू करती है। जब कंपकंपी छूटने जैसे दूसरे लक्षण दिखने शुरू होते हैं।

कहां फैला है 'मंकी फीवर'

1. महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और मामलों में लगातार गिरावट आ रही है।
2. लेकिन, रूस के कंज्यूमर वॉचडॉग रोस्पेट्रेब्राइजोर ने भारत के पूर्वी तटीय इलाकों में जानेवाले पर्यटकों के लिए चेतावनी जारी की है।
3. पिछले हफ्ते जारी एक रिपोर्ट में कहा गया- "लेबोरेटरी टेस्ट में सिंधुदुर्ग जिले के अंदर 332 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें से 19 मामले घातक थे"।

कैसे फैलता है मंकी फीवर?

1. मंकी फीवर लोगों से एक दूसरे में नहीं फैलता है। बल्कि, संक्रमित जानवरों का पंजा लगने या उसके संपर्क में आने से होता है, खासकर बंदरों से।
2. दक्षिण भारत के तीन क्षेत्रों को इस बीमारी के लिए बेहद संवेदनशील माना गया है। मंकी फीवर से पीड़ित ज्यादातर मरीज एक या दो हफ्ते में ठीक हो जाते हैं।

क्रिप्टो करेंसी अमीरों की सूची

फोर्ब्स ने पहली बार क्रिप्टो करेंसी रखने वाले अमीरों की सूची जारी की है। इस सूची में उन लोगों के नाम हैं जिनके पास मूल्य के हिसाब से करोड़ों अरबों डॉलर की क्रिप्टो करेंसी है। इस सूची में रिपल के सह-संस्थापक क्रिस लार्सन सबसे आगे हैं। लार्सन की क्रिप्टो मुद्राओं का मूल्य 7.5 से 8 अरब डॉलर है। बिना नियमन वाली क्रिप्टो मुद्राओं के मूल्य में हाल के समय में जोरदार तेजी आई है। यह ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के आधार पर गोपनीय एल्गोरिदम के हिसाब से काम करती है। फोर्ब्स के अनुसार क्रिप्टो मुद्राओं बिटकॉइन, एथेरियम और एक्सआरपी के औसत मूल्य में 2017 में 14,409 प्रतिशत का जोरदार उछाल आया है। ये तीनों मुख्य क्रिप्टो मुद्राओं में हैं।

क्या है

1. फोर्ब्स के अनुसार करीब 1,500 क्रिप्टो मुद्राएं इस समय चलन में हैं जिनका कुल मूल्य 550 अरब डॉलर है। 2017 की शुरुआत से इनके मूल्य में 31 गुना का इजाफा हुआ है।
2. फोर्ब्स के संपादक रैंडल लेन ने कहा कि इस तरह की संपदा को सामने लाया जाना चाहिए।
3. इस सूची में 1.5 अरब डॉलर के क्रिप्टो मुद्रा मूल्य के साथ जोसेफ ल्यूबिन दूसरे स्थान पर हैं। चांगपेंग चाओ 1 से 1.2 अरब डॉलर के साथ तीसरे, कैमरन एंड टायलर विंकलवास 90 करोड़ से 1.1 अरब डॉलर के साथ चौथे और मैथ्यू मेलन 90 करोड़ से 1.1 अरब डॉलर के साथ पांचवें स्थान पर हैं।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल से मांगा जुर्माना

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सर्च इंजन गूगल पर 136 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। सीसीआई ने गूगल पर यह जुर्माना ऑनलाइन सर्च के लिए भारतीय बाजार में अनुचित व्यावसायिक व्यवहार के लिए लगाया है। गौरतलब है कि सीसीआई भारत की एक विनियामक संस्था है, जिसका उद्देश्य देश में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है।

क्या है

1. सीसीआई ने यह आदेश उस शिकायत पर कार्यवाही करते हुए पारित किया है जिसे साल 2012 में दर्ज कराया गया था।
2. नियामक ने कहा कि गूगल पर यह जुर्माना “विश्वास-विरोधी आचरण का उल्लंघन” करने के लिए लगाया जा रहा है।
3. विश्व स्तर पर, यह दुर्लभ मामलों में से एक है जहां गूगल को अनुचित व्यावसायिक तरीके का इस्तेमाल करने के लिए दंडित किया जा रहा है।
4. सीसीआई ने अपने आदेश में कहा है कि गूगल को सर्च में पक्षपात करने का दोषी पाया गया है और ऐसा करने से इसके प्रतिस्पर्धियों के साथ ही साथ यूजर्स को भी नुकसान हुआ है।
5. आयोग ने कहा है कि गूगल को जुर्माने की राशि 60 दिनों के भीतर जमा करानी होगी। गूगल पर यह आरोप था कि वह सर्च में भेदभाव और सर्च में छेड़छाड़ करने के जरिये ऑनलाइन सर्च बाजार में अपनी प्रभावकारी बाजार स्थिति का गलत फायदा उठा रही है।

यौन उत्पीड़न कानून लागू करने के लिए SC ने मांगे सुझाव

कार्यस्थलों विशेषकर प्राइवेट सेक्टर में महिलाओं के साथ होने वाले यौन दुर्व्यवहार को रोकने के लिए केंद्र ने कानून लागू करने की योजना बनायी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ से इसके लिए सुझाव मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी 2018 को एनजीओ इनिशिएटिव फॉर इनक्लुशन फाउंडेशन (आईआईएफ) से कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कानून के प्रभावी कार्यान्वयन पर सुझाव मांगे।

क्या है

1. केंद्र द्वारा हलफनामे में कार्यस्थलों पर यौन दुर्व्यवहार से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2013 के लागू किए जाने को लेकर कदम उठाए जाने के दावे के बाद चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए. एम. खानविल्कर और जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ के बेंच ने सुझाव मांगे।
2. आईआईएफ के लिए मौजूद सीनियर काउंसिल संजय पारीख ने कहा कि प्राइवेट कंपनियों में ऐसा कोई कानून नहीं है। उन्होंने बताया कि चार साल पहले एसोचौम के साथ मीटिंग हुई थी लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ।

आईसीसी बोर्ड की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने भारतीय मूल की इंद्रा नूई को बोर्ड की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक नियुक्त किया है। इंद्रा नूई वर्तमान में पेप्सिको की चेयरमैन और सीईओ हैं। नूई इसी साल जून में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगी। नूई विश्व की ताकतवर महिलाओं में से एक हैं। आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर ने कहा है कि आईसीसी में नूई का स्वागत कर हमें खुशी हुई है। नूई ने कहा कि क्रिकेट को मैं हमेशा से ही पसंद करती रही हूँ। इसे मैंने कॉलेज समय में खेला था। ये हमेशा ही टीमवर्क, सम्मान और एक अच्छी चुनौती देना सिखाता है।

क्या है

1. चेन्नई में पैदा हुई इंद्रा नूई की आरंभिक शिक्षा दीक्षा भी चेन्नई में ही हुई है। विज्ञान विषयों से ग्रेजुएशन करने वाली इंदिरा ने बाद में कोलकाता के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से मैनेजमेंट की पढ़ाई की और भारत में ही अपना करियर शुरू किया।
2. कुछ वर्षों तक काम करने के बाद इंद्रा पढ़ाई करने के लिए अमरीका गईं और वहां येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से उन्होंने पढ़ाई की। कई कंपनियों में काम करने के बाद 38 वर्ष की उम्र में 1994 में इंद्रा ने पेप्सिको ज्वाइन किया।
3. 10 साल के बाद 2004 में कंपनी की मुख्य फाइनेंस अधिकारी और 2006 में वो कंपनी की सीईओ बनीं। वर्ष 2007 में उन्हें भारत का प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान भी मिल चुका है।

आधार नंबर को रद्द करने का किसी नागरिक को अधिकार नहीं

अगर आप आधार में पंजीकृत हो चुके हैं तो यह जान लीजिये कि कोई नागरिक इसे रद्द नहीं करा सकता है, यानी आधार को चाहकर भी नहीं छोड़ सकता है। कानून में ऐसा अधिकार नागरिक को नहीं दिया गया है, इसलिए ऐसा करना मुमकिन ही नहीं है। जैसे जन्म प्रमाण पत्र, कॉलेज-स्कूल डिग्री या पासपोर्ट का विस्तार नहीं खत्म कराया जा सकता। पूर्वोत्तर के मेघालय समेत देश में कई स्थानों पर हजार से भी ज्यादा लोग आधार को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर विशिष्ट पहचान-पत्र प्राधिकरण के मुताबिक आधार में पंजीकरण या निजी जानकारी अपडेट कराना आधार अधिनियम-2016 के तहत मान्य है। देश का कोई नागरिक 12 अंक के विशिष्ट पहचान नंबर यानी आधार में पंजीकरण के बाद बाहर नहीं निकल सकता है। अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

क्या है

1. प्राधिकरण के अनुसार किसी भी नागरिक को देश के कानून से बाहर निकलने का अधिकार नहीं है। कुछ लोग आयकर अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं और वे शायद पैनकार्ड डाटा खत्म कराना चाहें, क्या वे ऐसा कर सकते हैं? या क्या वे जन्म प्रमाण-पत्र, कॉलेज-स्कूल डिग्री या पासपोर्ट विस्तार से बाहर (खत्म) आने का आवेदन कर सकते हैं? मेघालय में इस मसले पर लोग अभियान चला रहे हैं।
2. प्राधिकरण के मुताबिक सरकार द्वारा देश के आर्थिक तंत्र संबंधी सेवाएं बेहतर, पारदर्शी, कुशल और प्रभावी तरीके से प्रदान करने के लिए आधार प्रणाली का इस्तेमाल देश के सभी लोगों के लिये किया जा रहा है। इसके साथ ही देश के विकास और अर्थव्यवस्था में आगे बढ़कर योगदान देना भी शामिल है।
3. आधार की क्षमता में बदलाव लाने और लोगों के सशक्तिकरण में विशिष्ट पहचान की पुष्टि ध्यान में रखते हुए है। गौरतलब है कि यूआईडीएआई के अनुसार आधार कानून और संस्कृति को प्रभावित किये बिना लोगों को सीधे

- लाभ पहुंचा रहा है। यह नागरिक और सरकार के बीच पारदर्शी शासन की ऑनलाइन व्यवस्था है। इसमें सेंध लगने की संभावना लगभग शून्य है जो योजनाओं पर आधारित है।
- सरकार का निर्णय है कि सुशासन के लिए भ्रष्टाचार मुक्त तंत्र और सीमित उपलब्ध संसाधनों से बेहतर सुरक्षित भारत बनाया जाए जिसमें कोई भी पीछे नहीं छूटे और विकास का लाभ वंचित लोगों को मिले। वास्तविक हकदारों को सेवाओं, सब्सिडी का लाभ सीधे उनके बैंक खातों में बिना किसी मुश्किल के जरिये भेजा जा रहा है।
 - आधार की संभावनाओं का फायदा उठाने के लिए टैक्स अनुपूरक समाज बनाने और समाज के हाशिये पर रहने वालों को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है।

अबू धाबी में पहले हिन्दू मंदिर की आधारशिला

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पहले हिन्दू मंदिर की आधारशिला रखे जाने के समारोह की आधिकारिक शुरुआत की। इस देश में भारतीय मूल के करीब 30 लाख लोग रहते हैं। प्रधानमंत्री आधारशिला रखे जाने के आयोजन के साक्षी बने जिसे दुबई के ओपरा हाउस में लाइव स्ट्रीम किया गया। प्रधानमंत्री, ओपरा हाउस में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस भव्य मंदिर के लिए 125 करोड़ भारतीयों की ओर से शहजादा मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को धन्यवाद दिया।

क्या है

- मंदिर समिति के सदस्यों ने मोदी और शहजादा मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को मंदिर से जुड़ा साहित्य भेंट किया। दुबई-अबू धाबी राजमार्ग पर बनने वाला यह अबू धाबी का पहला पत्थर निर्मित मंदिर होगा। प्रधानमंत्री की यह दूसरी यूएई यात्रा है, पहली बार वह वर्ष 2015 में यहां आये थे।
- अबू धाबी में प्रथम हिंदू मंदिर 55,000 वर्ग मीटर भूमि पर बनेगा। मंदिर का निर्माण भारतीय शिल्पकार कर रहे हैं। यह 2020 में पूरा होगा और यह सभी धर्म के लोगों के लिए खुला रहेगा।
- बोचासनवासी श्री अक्षर पुरषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (बीएपीएस) 1907 में स्थापित सामाजिक-आध्यात्मिक हिन्दू संगठन है।
- यह पूरी दुनिया में 1,100 से ज्यादा मंदिरों और सांस्कृतिक परिसरों की देखरेख करता है।

चुनाव आयोग कहा कि दागी नेताओं को दल बनाने से रोकें

आपराधिक मामलों में दंडित होने के बाद चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किए गए नेताओं के लिए नई पार्टी बनाना या पार्टी में किस पद पर रहना मुश्किल होगा। भारतीय निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि ऐसे नेताओं को पार्टी बनाने से रोकने के लिए दायर याचिका का वह पूरा समर्थन करता है। सुप्रीम कोर्ट में दायर 70 पन्नों के शपथपत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा कि दलों में आंतरिक प्रजातंत्र बेहद जरूरी है और इसे लागू करने के लिए निर्वाचन आयोग को कानूनी शक्तियां दी जानी चाहिए।

क्या है

- निर्वाचन आयोग के निदेशक (विधि) विजय कुमार पांडे ने यह शपथपत्र अश्वनी उपाध्याय की एक रिट याचिका के जवाब में दाखिल किया है। याचिका में मांग की गई है कि दंडित नेताओं को राजनैतिक दल बनाने और दलों में पदों पर रहने से रोका जाए।
- एक ओर तो अपराधों में दंडित होने के बाद वे छह वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिए जाते हैं लेकिन दूसरी ओर वे राजनैतिक दलों में पदों पर बने रहते हैं और अपनी पार्टी बना लेते हैं, जिससे आपराधिकरण जारी रहता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को विचार के लिए स्वीकार करते हुए 1 दिसंबर 2017 को केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
- आयोग ने शपथपत्र में कहा कि एक बार नहीं बल्कि चार बार चुनाव आयोग ने सरकार को चुनाव सुधार प्रस्तावों में राजनीति के आपराधिकरण को रोकने के लिए आयोग को शक्तियां देने के लिए लिखा है।

5. पहली बार 1998 में उसके बाद 2004 में फिर 2010 में तथा हाल ही दिसंबर 2016 में आयोग ने सरकार को प्रस्ताव दिए। जिसमें यह भी मांग की गई है कि आयोग को राजनैतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति होनी चाहिए।
6. आयोग ने कहा इतना ही नहीं 2002 में संविधान समीक्षा आयोग ने तथा उसके बाद राज्यसभा की स्थाई समिति ने 2005, 2013 में निर्वाचन आयोग को दलों को डीरजिस्टर करने की शक्ति देने के लिए कानून में संशोधन करने की सिफारिश की। जिसमें कहा गया था, यदि कोई दल लगातार 10 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ रहा है उसे डीरजिस्टर कर देना चाहिए।
7. आयोग ने हलफनामे में कहा, राष्ट्रीय विधि आयोग ने भी अपनी 255वीं रिपोर्ट में आयोग को दलों के अंदरूनी लोकतंत्र की निगरानी करने तथा दलों को डीरजिस्टर करने की शक्तियां देने के लिए जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 29ए में संशोधन करने की सिफारिश की।
8. आयोग ने शपथपत्र में कहा कि हालांकि आयोग ने स्वयं कार्रवाई करते हुए फरवरी 2016 में लगभग 255 ऐसे राजनैतिक दलों को गैरसूचित (डीलिस्ट) कर दिया था जिनका जमीन पर कोई अस्तित्व नहीं था। इनके बारे में कर विभाग, सीबीडीटी को सूचना भेजी गई थी कि उन्हें आयकर में कोई छूट न दी जाए।

2005 के विस्फोट से ही सुलग रहा बैरन आइलैंड

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों ने हाल ही में किए गए एक अध्ययन में निष्कर्ष निकाला है कि बैरन आइलैंड ज्वालामुखी से 2017 में जो लावा निकला था वह दरअसल 2005 के ज्वालामुखी विस्फोट का ही सिलसिला है। ध्यान रहे कि बैरन आइलैंड भारत और दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित है। इस ज्वालामुखी में पहला बड़ा विस्फोट 1787 में हुआ था। करीब 150 वर्ष तक शांत रहने के बाद यह 1991 में फिर फटा था। तब से इस ज्वालामुखी में बीच-बीच में सक्रियता दिख रही है। ताजा गतिविधि की जानकारी वैज्ञानिकों ने जनवरी 2017 में दी थी। ये वैज्ञानिक वहां ज्वालामुखी गतिविधियों का अध्ययन करने गए थे। वर्तमान अध्ययन में वैज्ञानिकों ने 2005 से 2017 तक ज्वालामुखी क्षेत्र में हुए परिवर्तनों और लावा के प्रवाह के मार्ग को समझने के लिए उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया।

क्या है

1. द्वीप के छोटे भू क्षेत्र और आसपास के समुद्र के कारण राडार तकनीकों से ज्वालामुखी की त्रिआयामी तस्वीर बनाना मुश्किल था। अतः वैज्ञानिकों ने ज्वालामुखी के आकार में हुए परिवर्तनों की पहचान करने के लिए विजिबल, शार्ट-वेव इंफ्रारेड और थर्मल इंफ्रारेड बैंड्स में हासिल की गई तस्वीरों का प्रयोग किया।
2. ज्वालामुखी के लावा, राख और गैसों उगलने वाले सक्रिय छिद्र के चारों तरफ बना गड्ढा ज्वालामुखी विस्फोट की निशानी है।
3. उपग्रह की तस्वीरों से पता चलता है कि जनवरी 2017 में जो छिद्र सक्रिय थे वे उस गड्ढे में स्थित हैं, जो 2005 में हुए विस्फोट से बना है, न कि 1991 में हुए विस्फोट से।
4. इससे इस बात की पुष्टि होती है कि हाल में देखी गई ज्वालामुखी गतिविधि 2005 में हुए विस्फोट का ही विस्तार है। वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया कि 2005 के विस्फोट ने लावा के प्रवाह के लिए तीन अलग-अलग दिशाओं में मार्ग बनाए। पहले लावा सिर्फ पश्चिम दिशा में बह रहा था। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि कर दी कि 2005 के विस्फोट के बाद ज्वालामुखी से लावा की निकासी बढ़ गई है।
5. ज्वालामुखीय विस्फोटों से निकलने वाली विषाक्त गैसों, राख और लावा का वनस्पति पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है और यह जगह जानवरों के रहने के लिए उपयुक्त नहीं रहती। इन विस्फोटों से वायुमंडल में उत्सर्जित होने वाली कार्बन डाईऑक्साइड और सल्फर डाईऑक्साइड से प्रदूषण बढ़ता है।
6. ज्वालामुखी कब फटेगा, इसका पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन इन विस्फोटों की निरंतर निगरानी करने से विस्फोटों के कारणों और परिणामों के बारे में हमारी समझ बढ़ती है और हम इनसे होने वाले नुकसान को कम करने के बेहतर उपाय खोज सकते हैं।

7. इस अध्ययन के नतीजे बुलेटिन ऑफ बोलकेनोलॉजी में प्रकाशित हुए हैं। रिसर्च टीम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नेशनल रिमोट सेंसिंग केंद्र और जियोसाइंस के वैज्ञानिक तपस आर. मार्था, प्रियम रॉय और के. विनोद कुमार शामिल थे।

भारत ने रचा इतिहास

भारत ने द.अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीत ली है। इसके साथ ही भारत ने एक इतिहास रचा है। 26 साल में पहली बार भारत ने द. अफ्रीका में 6 मैचों की सीरीज पर 4-1 से कब्जा किया है। सीरीज के पांचवें मैच में भारत ने द.अफ्रीका को 73 रनों से हराया है। इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 275 रनों का लक्ष्य दिया था। जिसका पीछा करते हुए द. अफ्रीका ने 201 रन ही बनाए। भारत ने सीरीज के पहले तीन मैचों पर लगातार जीत दर्ज की थी। इसके बाद चौथे मैच में द. अफ्रीका ने भारत को हराया था। लेकिन द. अफ्रीका पांचवां वनडे मैच नहीं जीत पाई।

क्या है

1. दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उनके शुरुआती तीन विकेट (एडेन मारक्रम, जेपी डुमिनी और जेपी डुमिनी) धड़ाधड़ गिरे। इसके बाद हाशिम अमला और डेविड मिलर ने पारी को संभाला और स्कोर को 127 तक लेकर गए। लेकिन 26वें ओवर में मिलर अपना विकेट खो बैठे।
2. भारत : विराट कोहली (कप्तान), शिखर धवन, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पंड्या, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, शार्दूल ठाकुर।
3. दक्षिण अफ्रीका : एडिन मार्करम (कप्तान), हाशिम अमला, अब्राहम डिविलियर्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), ज्यां पॉल ड्यूमिनी, फरहान बेहरदीन, इमरान ताहिर, हेइनरिक क्लासेन, डेविड मिलर, मोर्ने मोर्कल, क्रिस मौरिस, लुंगी नगिडी, आदिले फेहुलकवायो, कागिसो रबादा, तबरेज शम्सी, खायो जोंडो।

देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला

पहले से ही कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे देश के सरकारी बैंकों को अब इतिहास के सबसे बड़े घोटाले से निपटना होगा। सरकारी क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने यह राज उजागर किया है कि उसके मुंबई स्थित एक शाखा में 1.77 अरब डॉलर (11,346 करोड़ रुपये) का घोटाला हुआ है। इस घोटाले की आंच दूसरे बैंकों तक भी जाएगी। इस घोटाले के तार भी रत्न व आभूषण के प्रसिद्ध कारोबारी नीरव मोदी से जुड़े हुए हैं जिनके खिलाफ पीएनबी ने एक पखवाड़े पहले 280 करोड़ रुपये के फ्राड का आरोप लगाते हुए जांच सीबीआइ को सौंपी है।

क्या है

1. पीएनबी की तरफ से शेयर बाजार को सूचना दे कर अपनी एक शाखा में की गई इस धांधली के बारे में जानकारी दी। यह मामला वर्ष 2010 से चल रहा था।
2. बैंक ने बताया है कि, “उसने मुंबई स्थित अपनी एक शाखा में कुछ गड़बड़ी दर्ज की है। कुछ खाताधारकों को लाभ पहुंचाने के लिए लेन देन की गई है।”
3. इन लेन देन के आधार पर ग्राहकों को दूसरे बैंकों ने विदेशों में कर्जे दिए हैं। इस लेन देन का आकार 1.77 अरब डॉलर है। इसकी सूचना जांच एजेंसियों को दी गई है ताकि कानून के तहत दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
4. पीएनबी की तरफ से इस सूचना के आने के साथ ही वित्त मंत्रालय और पूरे बैंकिंग क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। वित्त मंत्रालय ने पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब की है।
5. वित्त मंत्रालय के बैंकिंग विभाग में संयुक्त सचिव लोक रंजन के मुताबिक, ‘यह एक बड़ा मामला नहीं है और ऐसी स्थिति नहीं है जिसे कहा जाए कि हालात काबू में नहीं है।’ लेकिन वित्त मंत्रालय के अन्य अधिकारी इस बात से चिंतित हैं कि इसके तार कुछ दूसरे सरकारों से भी जुड़े हुए हैं।

6. यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक और निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक ने भी पीएनबी की तरफ से गड़बड़ी करने वाले खाताधारकों को जारी आशय पत्र (एलओयू) के आधार पर कर्ज दिए हैं। ऐसे में जांच के दायरे में ये बैंक भी आएंगे।
7. एलओयू एक बैंक शाखा की तरफ से दूसरे बैंक शाखा को जारी एक ऐसा प्रपत्र है जो निश्चित खाताधारकों के पक्ष में दी गई एक गारंटी होती है। इसके आधार पर दूसरे जगह स्थित बैंक शाखा उस ग्राहक को कर्ज की सुविधा देती है।
8. बैंकिंग क्षेत्र के सूत्रों का कहना है कि जब नीरव मोदी मामले की जांच की गई तब इस तरह के दूसरे घोटाले का पता चला। नीरव मोदी व अन्य ग्राहक पीएनबी की उक्त शाखा से हासिल एलओयू के आधार पर दूसरे देशों में कर्ज हासिल करता था।
9. यह काम वर्ष 2010 से ही चल रहा था। ग्राहक इस कर्ज को समय पर चुका रहे थे जिससे किसी को पता नहीं चल रहा था। लेकिन हाल ही में नीरव मोदी की कंपनी ने कर्ज का भुगतान नहीं किया। इसके पीछे की कहानी यह बताई जा रही है कि गड़बड़ी में शामिल पीएनबी के अधिकारियों ने ज्यादा मार्जिन मनी की मांग की।

अब तक नाकाम रहे NPA वसूली के सभी उपाय

अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बने फंसे कर्ज यानी एनपीए की वसूली के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) को लेकर भले ही बड़ी उम्मीदें हों लेकिन हकीकत यह है कि एनपीए ऐसा मर्ज है जिसके इलाज के लिए अब तक किए गए नुस्खे नाकाम रहे हैं। हाल के वर्षों में एनपीए की वसूली के आंकड़े हकीकत बयां करते हैं। आइबीसी की शुरुआत भी कुछ खास उत्साहजनक नहीं है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में लोक अदालतों, डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन ट्रिब्यूनल (डीआरटी) और सरफेसी कानून का इस्तेमाल कर एनपीए की वसूलने की कोशिशें परवान नहीं चढ़ पाई हैं।

क्या है

1. वर्ष 2012-13 में लोक अदालतों, डीआरटी और सरफेसी कानून के तंत्र के जरिये 10.44 लाख मामले सुलझाने का प्रयास हुआ जिनमें 1057 करोड़ रुपये राशि फंसे कर्ज की थी। इसमें से मात्र 233 करोड़ रुपये की फंसे कर्ज की राशि ही वसूल हो सकी। खास बात यह है कि बीते वर्षों में वसूली के इस आंकड़े में लगातार गिरावट हुई।
2. वर्ष 2016-17 में डीआरटी, लोक अदालतों और सरफेसी कानून के जरिये 22.61 लाख मामलों को सुलझाने का प्रयास हुआ जिनमें 2860 करोड़ रुपये कर्ज फंसा था। इसमें से मात्र 10 प्रतिशत फंसे कर्ज की वसूली ही हो पायी। एनपीए वसूली का यह रिकॉर्ड अब तक के उपायों की नाकामी दर्शाता है।
3. यही वजह है कि सरकार को दिवालियेपन पर कानून बनाना पड़ा। आइबीसी के जरिये फंसे कर्ज की वसूली को लेकर बहुत उम्मीदें हैं।
4. आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में भी कहा गया है कि आइबीसी में हर उपाय के लिए समय सीमा निर्धारित है। इसलिए यह प्रभावी साबित होगा। हालांकि शुरुआती संकेत मिल रहे हैं कि फंसे कर्ज की वसूली में दिवालियेपन पर नया कानून भी बहुत उत्साहजनक परिणाम नहीं दे पाया है।
5. दरअसल पहले चरण में फंसे कर्ज वाली जिन 12 कंपनियों की परिसंपत्तियां बेचकर कर्ज वसूली की प्रक्रिया शुरू की गयी है, वे मामले कई तरह के झमेले में फंस गए हैं। बैंकों के अधिकारी अब यह बात स्वीकार करने लगे हैं कि दिवालियेपन पर कानून से भी कुल फंसे कर्ज का एक चौथाई से अधिक वसूली होने के आसार नहीं हैं।